

RAJYA SABHA

*Friday, 28th February 1958*

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

**LEAVE OF ABSENCE TO SHRIN.  
RAMAKRISHNA IYER**

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that the following letter dated the 22nd February, 1958, has been received from Shri N. Rama-krishna Iyer:

"I sustained fracture in my right leg in a motor accident on 5th January, 1958. My leg is in plaster and I am confined to bed. I have to remain so, under medical advice, for a month more. Consequently I am unable to attend the Twentieth Session of the Sabha. I request you to get the permission of the Sabha to be absent from the meetings of the Rajya Sabha in its Twentieth Session."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Iyer for remaining absent from all meetings of the House for the current session?

*(No hon. Member dissented.)*

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

**RESOLUTION REGARDING RESER-  
VATION OF SEATS FOR SCHED-  
ULED CASTES AND SCHEDULED  
TRIBES IN PARLIAMENT AND  
STATE LEGISLATURES—*continued.***

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajabhoj, you have taken 17 minutes; you have 13 minutes more. 120 RSD—1

**श्री पा० ना० राजभोज ( मुम्बई ) :**  
यह प्रस्ताव मेरे लिए बहुत अहम है और  
मेरे इसे समय पर सभ्यः कर दूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Yes, but still 13 minutes.

**श्री पा० ना० राजभोज :** सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है, उस में लिखा हुआ है कि असुस्थता का अंत किस तरह से और किस रूप में किया जाना चाहिये ।

"असुस्थता को किसी भी रूप में बरतना अपराध होगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।"

इसके अनुसार हमारे देश में असुस्थता को दूर करने के लिए कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद जितना उसका प्रभाव देहात में होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है । इसका कारण यह है कि इस संबंध में जो कुछ भी कार्य शुरू किया गया है, उसे आरम्भ हुए दो-चार ही वर्ष हुए हैं और गवर्नमेंट का ध्यान भी पिछले दो-तीन वर्षों से ही इस समस्या की ओर गया है । अभी तक जो कार्य हुआ है, वह केवल प्रोपेगण्डा की दृष्टि से हुआ है, कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से कई प्रकार का काम होना अभी बाकी है और आवश्यक है । हमारे विधान में इस संबंध में कई बातें लिखी हैं, लेकिन सरकार के सब काम विधान के मुताबिक पूरे नहीं हुए हैं । लास्ट टाइम जब मैंने इस संबंध में भाषण दिया था तो कहा था—कई प्रकार के लोगों का भी कहना है—कि इस संबंध में अभी तक हरिजनों के लिए कई प्रकार के कार्य करने हैं और उनकी आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार से उन्नति होनी बाकी है । इसके साथ ही साथ उन लोगों का ख्याल यह भी है कि हरिजनों को भलाई के लिए

[श्री पा० ना० राजभोज]

ज्यादा से ज्यादा अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के लिए हमारे संविधान की धारा ३३५ में यह लिखा है :

“संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।”

इस बात को सदन के सब सदस्यों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि संविधान में किस तरह का आश्वासन दिया हुआ है। इसी संविधान की धारा ३३८ में यह लिखा है : “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।” वह पदाधिकारी नियुक्त भी हो गया है और वह समय समय पर अपनी रिपोर्ट देता है। मगर देखने में यह आता है कि स्टेट सरकारें अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा नहीं रही हैं।

सभापति महोदय, संविधान की धारा ३३८ के दूसरे हिस्से में यह लिखा है :

“अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधि-

कारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।”

इसी अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिन को राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद ३४० के खण्ड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी है।

सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने संविधान की धारा ३३९ (१) रखना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है :

“प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्ट्रपति किसी समय कर सकेगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश में की जा सकेगी तथा उसमें वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध भी हो सकेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।”

तो मैं यहां पर दूसरी बात पदाधिकारियों के सामने बताना चाहता हूँ, वह यह है कि इसी धारा के भाग (२) में यह दिया हुआ है :

“संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे किसी राज्य को उस प्रकार के निर्देश देने तक होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखते हों।”

हमारे संविधान में पिछड़े वर्गों के बारे में कई बातें लिखी हैं। संविधान की धारा ३४१ में यह लिखा है :

“(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्, लोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के भागों या उनमें के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझी जायेंगी।

(२) संसद् विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिम जाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।”

कितनी अच्छी बातों का हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, लेकिन सभापति महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन सब बातों के अनुसार पूरा काम नहीं हुआ है।

हमारे संविधान की धारा ३४२ में यह लिखा है :

“(१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् लोक-अधिसूचना द्वारा उन आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति-समुदायों के भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिमजातियाँ समझी जायेंगी।

संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय को अथवा आदिमजाति या आदिमजाति-समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा।”

इस तरह की अच्छी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, जिसके द्वारा हम लोगों की भलाई हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इसी तरह का ख्याल हमारे और नेताओं का भी है कि इन चीजों से हम लोगों की भलाई बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त ने यह राय प्रकट की है कि १९६२ के बाद हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन आदिवासियों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो सुविधा अभी तक मिली हुई है, वह जारी रह सकती है। मेरी प्रार्थना आप से यह है कि हरिजनों में ही छत्रछाया की

[श्री पा० ना० भोज]

प्रथा बहुत ज्यादा आदिवासियों में यह प्रथा नहीं है। हरिजनों में बहुत सी जातियाँ हैं, जिनमें तरह तरह की बुराई फैली हुई है। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि जितना काम इन जातियों की भलाई के लिये होना चाहिये था, उतना अभी तक नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना आप से यह है कि आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में ठीक तरह से सुधार नहीं हुआ है। देहातों में उनकी दशा में कुछ भी अन्तर नहीं आया है। शहरों में थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, जैसे मंदिर खुल गये हैं, होटलों में जाने की इजाजत हो गई है। हरिजन सेवा संघ और भारत दलित सेवक संघ इस ओर थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन १० वर्ष की अवधि और बढ़ाना आवश्यक है। लेकिन यह कार्य अभी शुरू हुआ है। महात्मा गांधी के अन्त के बाद इस कार्य में बहुत रुकावट पड़ गई है। महात्मा जो गांव गांव घूमते थे, इसका प्रचार करते थे और प्रार्थना के समय इसकी चर्चा करते थे। गांधी जी के बाद विनोबा जी गांव गांव घूमते हैं। जो कार्य वे कर रहे हैं, वह मुझे बड़ा अच्छा लगता है; लेकिन जो काम वे करते हैं वह वे अधिकतर भूदान के बारे में करते हैं। वे चाहते हैं कि सब को जमीन मिलनी चाहिये। लेकिन हमारे देश की जो खास समस्या है वह ठीक तरह से हल नहीं हो रही है। एक स्थान में विनोबा जी ने कहा है :

“अस्पृश्यता निवारण का कार्य स्वतन्त्र भारत में भी बहुत कुछ करने

को बाकी है। हरिजनों को जब तक सामाजिक जीवन में सब तरह से बराबरी का दर्जा नहीं है, तब तक अपना देश स्वतन्त्र हुआ, ऐसा मान ही नहीं सकते। कानून में अस्पृश्यता नहीं रही, पर व्यवहार में भी वह नहीं रहनी चाहिये।”

उन्होंने इतने जोरदार शब्दों में कहा है और वे यह मानते हैं कि अस्पृश्यता व्यवहार में है। फिर आगे उन्होंने यह लिखा है :

“भूदान यज्ञ के सिलसिले में हम तीन साल से सतत पैदल घूम रहे हैं, तो गांव गांव की हालत देखने का मौका मिलता है। हरिजनों के लिये जगह जगह रुकावटें हैं। यह कितना अधर्म है, इसका भान हम लोगों को कराते हैं। भूदान यज्ञ का आरम्भ भी ता० १८ अप्रैल, १९५१ को पोचपल्ली गांव में हरिजनों की मांग पर ही हुआ था। तब से हमने यह असूल ही रखा है कि भूदान यज्ञ में जो जमीन मिलेगी, उसका काम से कम एक तिहाई हिस्सा भूमिहीन हरिजनों को देना है।”

मुझे आशा है कि इससे हरिजनों के उत्थान के लिये काफी मदद मिलेगी और उनकी बातों पर अमल किया जायेगा।

महाराष्ट्र के स्वर्गीय श्री काका साहेब बरवे ने अपनी किताब में कितनी ही बातें इस सम्बन्ध में लिखी हैं कि अभी अस्पृश्यता



का अन्त दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। एक स्थान में उन्होंने यह लिखा है :

“करीब २५ साल पहले की बात है, डा० अम्बेडकर साहब नानदेश के चालिसगांव स्टेशन पर आये। गांव में जाने के लिये उन्हें तांगे भी जरूरत थी। स्टेशन पर स्वागत के लिये कुछ हरिजन भाई पहुंचे थे। उससे तांगे वाले समझ गये कि डा० अम्बेडकर साहब एक हरिजन हैं। उन्होंने एक तांगा तो दे दिया किन्तु स्वयं चलाने में इन्कार कर दिया। फिर एक हरिजन भाई तांगा हांकने को बैठा, किन्तु वह अनजान होने के कारण ठीक नहीं चला सका और डा० साहब तांगे से गिर पड़े। इसी प्रकार की घटना माननीय श्री जगजीवनराम जी के साथ घटी, जब वे काशी विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० के छात्र थे। वे दाढ़ी बनवा रहे थे। बातचीत के दौरान में नाई को जैसे ही मालूम हुआ कि जगजीवन बाबू दलित वर्ग के सदस्य हैं तो वह काम अधूरा छोड़कर अमा याचना करता हुआ चला गया।”

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय ( मध्य प्रदेश ) : यह पुरानी बात है।

श्री पा० ना० राजभोज : यह पुरानी बात है, लेकिन नई बातें बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे सदन में कई प्रकार के सुधारक लोग हैं। कुछ पुराने ख्यालात के भी हैं। इसी महीने की ६ तारीख को मैंने इस हाउस के सामने रखा था कि दिल्ली के पास एक गांव है, जिसमें अभी हरिजनों को पानी भरने का मौका नहीं मिलता है। मुझे ज्यादा टाइम मिले तो मैं सब प्रकार की नई बातें आपके सामने रखूँ। शिड्यूल्ड कास्ट

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में श्री बान्सीकि जी ने कहा है कि आज भी देहातों में कोई हरिजन अच्छे कपड़े पहनता है, तो उससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। इन्हीं बातों के कारण मैंने पुरानी बात रखी। आज भी जब मैं कहता हूँ . . .

(Time bell rings.)

बड़ा ही इम्पार्टेंट विषय है।

MR. CHAIRMAN: Importance does not depend on the length of the speech.

श्री पा० ना० राजभोज : पांच-दस मिनट में सब हो जायेगा। रुपा करके थोड़ा टाइम दे दीजिये।

MR. CHAIRMAN: No. Hurry up. One minute.

श्री पा० ना० राजभोज : बहुत सी बातें हैं लेकिन सब बातें बताने के लिये मेरे पास समय नहीं है। मैंने गांधी जी के साथ कई वर्ष काम किया है। गांधी जी से जो मेरा पत्र-व्यवहार हुआ है, वह मैंने प्रकाशित किया है। हरिजनों को और सबकों को क्या करना चाहिये, ऐसी बातों के लिये मैंने उनसे सवाल पूछा था। जब तक सबको भाइयों के साथ हमारा सम्बन्ध है, दोस्ती है, तब तक ठीक है। आज आप देखिये कि हम यहां आपस में खान पान करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन देहातों में क्या परिस्थिति है। देहातों में बहुत ही खराब परिस्थिति है। इसी वास्ते मेरी प्रार्थना है कि यह प्रस्ताव पास होने का आवश्यकता है। मनुस्मृति और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में हरिजनों के विरुद्ध बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जिनको कानून के द्वारा बन्द करना चाहिये। तो मेरी यह प्रार्थना है कि धार्मिक ग्रंथों में अस्पृश्यता के सम्बन्ध

[श्री पा० ना० राजभोज]

में जो बहुत सी बातें भरी हुई हैं, उनके लिये गवर्नमेंट को कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

डा० अम्बेडकर साहब के साथ भी मैंने बहुत वर्षों तक काम किया। उन्होंने भी बहुत सी अच्छी बातें बताईं। यह दूसरी बात है कि कुछ बातों में हमारा उनका मतभेद रहा हो। मैं यह भी जानता हूँ कि जब से गृह-मंत्री पंत जी आये हैं, तब से थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है। पंत जी इस समय सदन से जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे स्टेट चीफ-मिनिस्टर को बुलायें और शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर को बुलायें और उनसे पूछें कि अच्छा काम क्यों नहीं होता है। इस सम्बन्ध में थोड़े दिन पहले एक कॉफ़ेंस हो चुकी है। तो जब से पंत जी होम मिनिस्टर हुये हैं तब से कुछ काम शुरू हुआ है। अभी बहुत काम बाकी है। इसलिये मैं दस वर्ष बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आज हिन्दी लैंग्वेज और दूसरी बातों के लिये समय बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन यह देखना चाहिये कि आज हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति क्या है। आज भी हमारा जीवन कुत्ते और जानवरों के सरीखा है। उत्तर के समय जब और समय मिलेगा तब मैं इस सम्बन्ध में और बातें बतलाने का प्रयत्न करूंगा। इस समय मेरा यही कहना है कि वे दस वर्ष बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि अभी हमारी स्थिति सुधरी नहीं है। पहले कई प्रकार के होम मिनिस्टर यहां हो चुके हैं, लेकिन वे कुछ ठीक काम करते नहीं थे। अब मैं यह चाहता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब सब चीफ मिनिस्टर से पूछें कि तुम्हारी स्टेट में क्या हो रहा है। आज स्टेट्स के मिनिस्टर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। क्या वजह है कि उनसे कोई प्रवृत्ति नहीं है। मेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीमें बनती रहती हैं लेकिन उन पर ठीक तरह से अमल नहीं

होता है। मिसेज अल्वा ने हरिजनों के सम्बन्ध में बहुत से आंकड़े दिये थे, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी के बारे में ठीक तरह से काम नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ज़मीन का बंटवारा भी हरिजनों के लिये ठीक तरह से नहीं हुआ है। हाउसिंग स्कीम और गंदी बस्तियों के बारे में हम लोगों को स्टेटिस्टिक्स मालूम होनी चाहिये। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर ने कई बातें लिखी हैं, लेकिन उन पर ठीक तरह से अमल नहीं हो रहा है। इर्मांलिये मेरा यह विचार है कि यह दस वर्ष बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। मैं नहीं चाहता कि यह जात-पात का मामला हमेशा रहे या हम हमेशा हरिजन या चमार आदि बने रहें। जब समाज में दूसरी जातियों के साथ हमारा दर्जा बराबरी का हो जायेगा तब हम किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं चाहेंगे। समय ज्यादा हो गया है, इस-लिये मैं अब समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Resolution  
moved:

"This House is of opinion that the period of reservation of seats in Parliament and in the State Legislatures provided for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Constitution should be extended from ten years to twenty years."

There is an amendment by Mr. Patil. He is not here. Therefore, it falls. The Resolution is before the House for discussion. Shrimati Lakhnapal.

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल ( उत्तर प्रदेश ) : सभापति महोदय, इस समय सदन के सामने जो प्रस्ताव विचाराधीन है, उसके द्वारा मांग की गई है कि संविधान में अनु-सूचित और जनजातियों को जो विशेषाधिकार दस साल के लिये दिये गये हैं, उनकी

मीमा को बढ़ा कर दस साल से बीस साल कर दिया जाये।

यह विषय ऐसा है कि प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहती हूँ कि प्रस्तावक महोदय ने जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ अपनी विचारधारा को सदन के सामने रखा है, उसमें किसी को भी उनकी सद्भावना में, उनके उत्साह में और उनकी जो अपनी जाति के लिये त्याग और प्रेम की भावना है, उसमें जरा भी शक नहीं है, सन्देह नहीं है; लेकिन फिर भी मैं उनसे थह प्रार्थना करूँगी कि ऐसे प्रस्ताव पर, ऐसे सम्मिलित विषय पर विचार करने से पहले वे इस विषय के सब पहलुओं पर विचार कर लें, तो ज्यादा अच्छा हो। जो पहलू मैं उनके सामने रखने वाली हूँ, वह उनसे भिन्न पहलू है, लेकिन इसके माने यह नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं का आदर नहीं करती हूँ, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। तो मेरा केवल यही अनुरोध है कि जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा दृष्टिकोण है, उस पर भी वे विचार करें और मेरा रुग्ण है कि फिर उसके बाद वे इस विषय के सम्बन्ध में ठीक निर्णय पर पहुँच सकेंगे।

धीमन्, कहा जाता है कि आमतौर से यह मांग इसलिये की जाती है कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं, उनकी हालत आज भी, सात आठ साल के बाद भी कोई अच्छी नहीं हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और जैसा कि अभी उनके द्वारा कहा गया है कि गांवों में हालत बहुत ज्यादा चिन्ताजनक है और वहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने इसका जो उत्तरदायित्व ज्यादातर भारत सरकार के ऊपर डाला है, यह बात मुझे कुछ ज्यादा जंची नहीं। मेरा ख्याल है कि उनकी हालत सुधारने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वह और लोगों पर भी है। आज जो हालत है वह ख़ास तौर पर क्या है? हमारे सामने जो हालत है, वह यह है कि हम देखते हैं कि

हरिजन कम्यूनिटी के कुछ थोड़े से टापमोस्ट मुखिया कहलाने वाले व्यक्ति या परिवार ही उन विशेषाधिकारों से लाभ उठाते हैं, ये ज्यादातर वही परिवार हैं जो कि चमकते और फलते-फूलते नज़र आते हैं। उद्देश्य तो यह होना चाहिये था और उनसे आशा भी यही थी कि उनकी कम्यूनिटी के बाकी और जो लोग हैं, उनको इन विशेषाधिकारों का भान कराते और उन तक उन भुविधाओं को पहुँचाते, लेकिन उनके अन्दर इतनी ज्यादा स्वार्थपरता मौजूद है कि वे उन विशेषाधिकारों को खुद ही हड़प जाना चाहते हैं और उनका भान दूसरों को होने तक नहीं देते। परिणाम यह होता है कि जिन व्यक्तियों तक इन विशेषाधिकारों को पहुँचना चाहिये था और जिन्हें उनकी विशेष ज़रूरत थी उन तक नहीं पहुँचता है और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वार्थ के वश में हो कर इनका यह इंटरेस्ट हो जाता है, यह हित हो जाता है कि उन गरीब, नादान, भोले भाले, अनपढ़ भाइयों को एक्सप्लायट करें, उनको वैसे ही गिरी हालत में रखें ताकि वे अपने रिजर्वेशन और विशेषाधिकार की मांगों को सदा जीवित बनाये रख सकें। यह वास्तव में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है लेकिन मैं समझती हूँ कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर ज्यादा है, जो कि अपने आप को मुखिया कर के मानते हैं और अपने को उनका ठेकेदार कहते हैं और अपने को अनुसूचित जातियों के हितों के रक्षक और ठेकेदार मानते हैं।

इस बारे में एक और भी ख्याल है . . .

श्री किशोरी राय (बिहार) : ठेकेदारी तो हरिजन सेवक संघ ने ली है, आप लोगों ने ली है।

श्री राजेश्वर अग्निभोज (मध्य प्रदेश) : आप लोगों ने ठेकेदारी ले ली है।

**श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल :** मैं आप सब भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि वे मेरे पूरे दृष्टिकोण को सुन लें और समझ लें और उसके बाद फिर मैं भी उनके दृष्टिकोण को समझने के लिये पूरी तरह से तैयार हूँ ।

**श्री किशोरी राम :** दृष्टिकोण तो हमारा आपके साथ है, आदर्श भिन्न है ।

**श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल :** एक बात यह भी कही जाती है कि हमने इन विशेषाधिकारों के द्वारा एक आकर्षण पैदा कर दिया है । हरिजनों को विशेषाधिकार दे कर एक प्रिविलेज क्लास, एक अलग सा क्लास बना दिया है और उसका नतीजा यह है कि आज जो ऊँची जाति के लोग हैं—ब्राह्मण तक भी—वे हरिजन बन जाना चाहते हैं । इस विषय में तो मेरा निजी अनुभव है । मेरे पास अक्सर कई विद्यार्थी आते हैं और वे कहते हैं कि उनको हरिजन होने का, शिड्यूल्ड कास्ट होने का, एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाये । असल में बात यह है कि हर एक जाति के अन्दर, चाहे वह ऊँची भी हो, इतने ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, इतने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं कि वे यह समझते हैं—चाहे वे ब्राह्मण हों, क्षत्रा हों या वैश्य हों—कि कितना अच्छा होता कि हम सभी को हरिजनों की सी विशेष सुविधायें प्राप्त हो जातीं ।

**श्री रामेश्वर अग्निभोज :** ठीक है, आप पोजीशन एक्सचेंज कर लीजिये । जितने मेंट्रल गवर्नमेंट में ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, उनकी जगह पर हरिजनों को मिनिस्टर बना दें और जितने हरिजन हैं, उतने ही ब्राह्मण कर दीजिये ।

**Exchange the position and I am prepared to leave the reservation. Exchange the position.**

**श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल :** श्री अग्निभोज जी बेकार को भड़क रहे हैं, मैं उससे पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि

यह जरूरी नहीं है कि यह विचारधारा मेरी अपनी है, लेकिन ये बातें हवा में हैं, वातावरण में हैं इसलिये इन सब विचारों का सामना करने से और उन पर अच्छी तरह से विचार कर लेने से हमको मदद ही मिलेगी ।

एक और विचार है और वह यह है कि हरिजनों के अन्दर उन विशेषाधिकारों के द्वारा एक पार्यंक्य की भावना पैदा होती जा रही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि जब ये अधिकार दिये गये थे, तो इनका उद्देश्य यह था कि यह सारी कम्युनिटी अपने को सुधार कर, अपने को ऊँचा बना कर ऐसी स्थिति में आ जाये कि हरिजनों के अन्दर और ऊँचा जातियों के अन्दर जो आज एक अलग-अलग की भावना है, जो एक पार्यंक्य की भावना है, उनके बीच में जो एक खाई है वह मिट जाये और वह हिन्दू समाज का एक अभिन्न अंग बन जाये । इन विशेषाधिकारों को देने का उद्देश्य यही था, लेकिन जो परिणाम आज हमारे सामने है वह यह है कि आज हरिजन कम्युनिटी में एक पार्यंक्य की भावना दृढ़ होती चली जा रही है । अलग अलग जो संस्थायें खोली जा रही हैं, जो हरिजन होस्टल, हरिजन छात्रावास, हरिजन स्कूल, हरिजन आश्रम आदि आदि खोले जा रहे हैं, ये हरिजनों के अन्दर और सवर्ण जातियों के अन्दर एक पार्यंक्य की भावना को लाने में और भा ज्यादा मदद दे रहे हैं ।

**श्री रामेश्वर अग्निभोज :** आप ज्यादा पैदा कर रही हैं ।

**श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल :** मैं समझती हूँ कि इसी खतरे को समझ कर अभी इस वेक्य पर विचार करने के लिये एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें यह विचार किया गया था कि हर एक होस्टल में, छात्रावासों में ऐसी भी व्यवस्था की जाये कि शिड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स भी रह सकें जो कि नान-शिड्यूल्ड कास्ट के हों जो कि सवर्ण जातियों के हों, जिससे कि नज़

दोनों वर्गों के अन्दर जो पार्थक्य का भावना आती जा रही है, वह न आये।

इसके अलावा एक और भी विचार है और वह यह है कि जातियों के आधार पर विशेषाधिकार दे कर कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जाति के भाव को ही, जाति के विचार को ही, हम एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं। असल में देखने में यह आया है कि ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों, जिनके अन्दर कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं होते, जो कि अशुद्धतन्त्र को मानते ही नहीं हैं उन लोगों की तरफ से भी . . .

श्री किशोरी राम : आपको पता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के ही लोग ईसाई बन रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : श्रीमन्, मैं इन इंट्रिक्स पर ध्यान न दे कर अपनी बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आप घंटी बजा देंगे और फिर मैं अपनी पूरी बात भी न कह सकूंगी।

ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों के अन्दर जात-पात नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इन सब लोगों की तरफ से एक आवाज उठाई गई है कि उनके अन्दर भी दलित जातियाँ हैं, उनके अन्दर भी हरिजन हैं और अगर हरिजन नहीं हैं, तो कम से कम इस प्रकार की पिछड़ा हुई जातियाँ हैं शिकरी, हालत हरिजनों से किसी हालत में भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इनके लिये विशेषाधिकार मांगा है और मैं समझती हूँ कि इस मांग में किसी हद तक काफ़ी सचाई थी और उस सचाई को मानते हुये ही भारत सरकार की ओर से एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की नियुक्ति हुई जिसकी अध्यक्षता हमारे इस सदन के माननीय सदस्य श्री काका कालेलकर जी ने की। उन्होंने, उस कमीशन ने, सारे देश के अन्दर टूर किया और जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी उसके अन्दर उन्होंने

२,३६६ ऐसे जातियों के नाम गिनाये जो कि बैकवर्ड और पिछड़ी हुई जातियाँ मानो जाती थीं। जब यह रिपोर्ट माननीय गृह-कार्य मंत्री, माननीय श्री पंत जी के सामने रखी गई, तब उन्होंने उस वक्त ठीक ही कहा था कि अपने देश के अन्दर इतनी अधिक बैकवर्ड जातियाँ हैं कि देश के ७५ फीसदी व्यक्ति बैकवर्ड कहे जा सकते हैं। श्रीमन्, जिस देश के अन्दर ७५ फीसदी लोग बैकवर्ड हों और जिस देश के अन्दर ६० फीसदी लोग अनपढ़ हों, वह सारा का सारा देश एक बैकवर्ड देश है, वह सारा का सारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है, ऐसा माना जाना चाहिये। और गृह-मंत्री ने तब यह भी कहा था कि जब सारा का सारा देश ही बैकवर्ड है, तो बैकवर्डनेस के आधार पर किस प्रकार से विशेषाधिकार दिये जा सकते हैं। तो, श्रीमन्, मैं यह सब बातें जो कह रही हूँ इनसे मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हरिजनों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनके मैं विरुद्ध हूँ। मैं तो यहां तक कहना चाहती हूँ कि हिन्दू समाज का हरिजन भाइयों के प्रति एक धार्मिक कर्तव्य है, एक पवित्र कर्तव्य है, एक पवित्र बोझा और जिम्मेदारी है और वह बोझा तब तक नहीं उतर सकता है, उस उत्तरदायित्व और धार्मिक बोझ से हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कि हरिजन हिन्दू समाज के अविभाज्य और अभिन्न अंग न बन जायें। श्रीमन्, इसी उद्देश्य से ये विशेषाधिकार संविधान के द्वारा दस साल तक के लिये दिये गये थे। उनका उद्देश्य यह था कि जो भेदभाव—एक अंतर, एक पृथक्ता, एक गैप—हरिजनों के अन्दर और सबर्ण जातियों के अंदर है, वह मिट जाये।

(Time bell rings.)

लेकिन, दुर्भाग्य का बात यह है कि इन विशेषाधिकारों की मर्यादा होती है, सीमा होती है और उस मर्यादा के अन्दर ही, सीमा के अन्दर

[श्रीमती चन्द्रवती लखनपाल]

ही, उन उद्देश्यों को, उन विशेषाधिकारों की उपयोगिता है। मैं आपके सामने यह निवेदन किया चाहती हूँ कि मेरी यह मान्यता है कि अगर सीमा के बाहर विशेषाधिकार को दिया जाये, तो उनकी उपयोगिता हानि में परिणत हो सकती है। श्रीमन्, जो विचार मने रखे हैं, यदि उनमें कुछ मजबूती है . . .

श्री रामेश्वर अग्निभोज : कम से कम आपको तो हानि होगी ही।

श्रीमती चन्द्रवती लखनपाल : श्रीमन्, एक रोगी, जब वह अच्छा होने लगता है और अच्छा होने के बाद जब वह चलना शुरू करता है, तो इसमें संदेह नहीं कि उसको डाक्टरों द्वारा यह एडवाइज दी जाती है, उसको यह अधिकार दिया जाता है कि वह लाठी का सहारा लेकर चलना मोखे। यह ठीक है कि शुरू में उसे लाठी दी जाती है, लेकिन अगर वह सदा ही लाठी लेकर चलता रहे, तो क्या वह कभी स्वतन्त्र रूप से चलना सीख सकेगा। इसी प्रकार से मेरा यह कहना है कि यदि विशेषाधिकार बहुत लम्बे असें तक हरिजन भाइयों और अनुसूचित जातियों को दिये जायें तो उनके अन्दर एक साइकोनाजो आफ डिपेंडेंस, एक पराश्रयता की भावना और मनोवृत्ति पैदा हो जाने का खतरा है।

श्रीमन्, जिस जाति के अन्दर आत्म-सुधार करने का इनिशियेटिव है, इच्छा और अभिलाषा है, अगर वह जीवन-मंश्राम में अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहती है, तो वह जाति विशेषाधिकारों के सहारे देर तक जीवित नहीं रह सकती। इसलिये मेरा यह कथन है कि प्रस्तावक महोदय इन सब बातों पर, जो मने उनके सामने रखी हैं, जो बातें कि हवा के अन्दर फैली हुई हैं, वातावरण के अन्दर हैं, जिनके कारण लोग हरिजन-आन्दोलन को गलत दृष्टिकोण

से देखने लगते हैं—शुद्धता कि मेरा उन पर विश्वास नहीं है, मेरी तो सद्भावना प्रस्तावक महोदय के साथ है—मैं चाहती हूँ कि वे उन पर विचार करें और उनके प्रकाश में वे अपने एक खास निर्णय पर आयें।

MR. CHAIRMAN: Mr. Agnibhoj, you can speak now, but don't get excited.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Very well, Sir. In the very beginning, Sir, I believe that this may be my last chance to speak on this subject in this House, and therefore I pray for your indulgence to put my point of view fully before this august House, and I shall try my best to be as calm, as cool, as reasonable and as argumentative as possible.

MR. CHAIRMAN: Quite right.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Sir, in the very beginning, by way of personal explanation I must say that I am a hundred per cent, nationalist. From the age of 13 years I joined the struggle for independence and worked with Sardar Patel, Mahatma Gandhi and our dear Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. I courted jails seven times, and from that day, i.e. the 13th of April, 1924, up to this day, without even a moments break, I am a Congressman—the Jalianwalla Bagh day.

Sir, I am a believer in human rights and dignity, and at the same time, I believe in a classless and a caste-less society. I am through and through nationalist and I want that my nation should prosper, should become greater and should be consolidated and honoured so that no power in this world can ever be able to raise even a little finger against my nation and against my country. Sir, the proof of my sincerity or making the nation casteless and classless is this: When I was a Minister in Madhya Pradesh, I got, according to Mahatma Gandhi's principles and

sayings, my two nieces married to Brahmin boys in 1950 and 1952, and, Sir, it should not surprise you that in the same way I live with a Brahmin lady even today. Therefore it can be seen that I am a believer in a casteless and a classless society. But, Sir, to my great surprise, to my great disappointment and to my great regret, I find that the nation—I may do anything, but the nation—is going in the back gear, not in the forward gear. Even the greatest people of my nation and responsible people think in a wrong direction and act in a way which is prejudicial to nationalism. Rather it is an anti-national action.

Sir, I must point out that I take the Constitution to be very sacred and I bow my head before the Constitution, because it has been drafted by the greatest minds and the greatest people of my nation. The wisest people of the day, the wisest Prime Minister of the day and the wisest and responsible people of the day, provided some protection to the minorities when they drafted the Constitution. Why did they do it? Because they thought that the people were depressed, the people were oppressed, the people were suppressed and they were poor, half-fed and half-naked, and they were not educated and therefore they were helpless. So, with these good and honest intentions the Constitution-framers provided some protection for the minorities and they provided for reservation for ten years. But, Sir, the reports of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been discussed here year after year, and I can give quotations from those reports to prove that the work of the Central Government, and particularly the State Governments, is far from satisfactory. Go through all the reports and you will find that the work done in this direction by the Government is far from satisfactory. Then, Sir, when that is so, are you going to take away these reservations and protections and leave us in conditions which are far from satisfactory? Do you want to

keep us in a condition which is admitted to be far from satisfactory? I don't think so. In that case what are you going to do?

Sir, I have got very great respect for motherhood, and especially in this House I have got very great regard and motherly feeling for the ladies throughout except one or two. Therefore, Sir, with my due respects and with due honour I want to contradict Shrimati Chandravati Lakhan-pal. I hope she would excuse me for doing so. She is sisterly to me and she is motherly to me; she is a great lady and a great nationalist. But when she says that we Harijans are responsible for these caste distinctions, she is totally wrong. Sir, we are not responsible for this separatism. It is the Hindu society, the caste-Hindu Society, and especially the Brahmin society, which is responsible for the depression, suppression and separation of the Scheduled Castes. When I go to *mandirs*, they drive me out of the temples. When I go to a well, do the Harijan people drive me away? Do the Harijan people believe in separation? It is the Brahmins and Pandits who take the *dunda* and drive me away, but you blame me and you blame the Harijans that we are responsible for this separation. No, we are not. You are responsible. If it is my fault to live with a Brahmin lady, for that you persecute me. Then, who is responsible? You or me? Sir, preaching is different from practice. So, I want to tell you that, though there is protection, still we are persecuted. When I spoke last on the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Home Minister, Mr. Datar, said that I was bitter and unfriendly. It is true:

"Satyam Bruyat Priyam Bruyat  
Apriyam Satyam Na Bruyat."

But it is my lot that I am required to tell the bitter truth. Truth is bitter and unfriendly. Therefore, I said that I have put on this white cap . . .

THE MINISTER OF REHABILITATION AND MINORITY AFFAIRS (SHRI MEHR CHAND KHANNA) : Where is it?

SHRI R. U. AGNIBHOJ: I am coming to you. You are a better man. I have had this white cap for 35 years, and if it is not now on my head, it is in my house, and I do not want that there should be any black spot on it, but at the same time I may submit that a black spot on the cap is not so material as the blackness of heart which is more dangerous in this country. I feel that people are dishonest in their professions. They are not sincere, they are not true to their profession that they want to uplift the Harijans and the backward classes, Adivasis and minorities. Who are the minorities? The proposition is true that the whole country is backward and suppressed and depressed. At the same time, it is true that it is a minority who rules the country, the minority people who are wise, who are active, who are people who want to crush and suppress the other minorities. They are ruling the country. If all the minorities of this country are united, they would turn themselves into the majority and the minority rule which is there would be thrown away. This communal caucus will be thrown away. That day will come if you do not mend your house, your minds and your actions. That day would come very soon, when the minorities would throw you overboard.

I tell you why we want constitutional protection and reservation. In the Lok Sabha there are so many Harijans and Adivasis, because there is reservation, but in this House there are five or six of whom one is Agnibhoj, and he is going to be butchered, yes, butchered. If your intentions are honest, if you are really sincere, let Agnibhoj go to hell, throw him into the street, but why don't you bring 40 Harijans into this House? If you are sincere, here is a test of your sincerity and honesty. Therefore, you are dishonest in your

professions—I mean the Government of India—and it has shaken my faith and I have got no confidence. I would pray to God, and our voice will not go in vain. I have got due respect to Him. You are creating anti-national feelings. You learn from Mahatma Gandhi. Mahatmaji and Thakkar Bappa have done so much for us and we are grateful to them. Thakkar Bappa was the greatest soul who served us, and you are anti-Thakkar and anti-Mahatma-ji, anti-national. Therefore, I say that looking to these circumstances, I would request my friend, Shrimati Chandravati Lakhanpal, and many friends like her to revise their opinion that we are responsible for this reservation. It is you, who are responsible, it is the higher caste caucus, who do not want us to live with self-respect and dignity. Therefore, with due respect to you, I say that Mr. Rajabhoj's Resolution should be accepted. Thank you.

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय : आदरणीय सभापति महोदय, यद्यपि यह प्रस्ताव ठीक भाषा में जमा नहीं है, किन्तु मैं उसके पक्ष में हूँ। मेरी राय यह है कि हरिजनों को जो दस साल का रिजर्वेशन दिया गया है, संविधान में संशोधन करके उसे बीस साल कर देना चाहिये। सभापति महोदय, मैं अपने इलाके में हरिजन कार्य बहुत समय से करता आ रहा हूँ। सबसे पहले जो हरिजन काँग्रेस शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जी उसके पक्ष में थे और सन् १९३२ के बाद यह काम देश में और भी तेजी के साथ किया जाने लगा। इससे पहले मैं अपने जिले में हरिजनों के सम्बन्ध में काँग्रेस और सभायें करता आ रहा था और उनके लिये कुछ न कुछ काम भी करता रहता था। आज जो हरिजन यहाँ नजर आते हैं, इस सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत काम होता है, वह हमारे संविधान की बुद्धिमत्ता के सबब से होता है। मैं कह सकता हूँ कि नौकरियों में, लेजिस्लेचरों में, या हमारे पार्लियामेंट में हरिजनों को जो रिजर्वेशन दिया गया है,



वह अनुचित नहीं है, उससे लाभ ही हुआ है। मुमकिन है कि कुछ हरिजन नेताओं में कुछ गलतियाँ हों। मुमकिन है कि कहीं कहीं कुछ स्वार्थी नेता पैदा हो गये हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको देकर कोई गलती की गई है। समाज में जो कमजोर होता है, उसको कुछ विशेषाधिकार दिये जाते हैं और उसको कुछ विशेष बर्ताव मिलता है। अभी हमारी बहिन श्रीमती लखनपाल ने पृथक्ता की भावना की शिकायत की। लेकिन यह भावना हरिजनों के सबब से नहीं है। यह भावना तो हमारे समाज के भीतर घुसी हुई है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो हरिजनों में भी है और दूसरे लोगों में भी है। यह हमारे समाज में एक कमजोरी है। आज आवश्यकता यह है कि जैसे कि एक छोटे बच्चे या डेलिक्वेंट चाइल्ड को डाक्टर एक महीने की दवा देता है और फिर जब एक महीने के बाद देखता है कि बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है, तो वह फिर कहता है कि एक महीने की और दवा दे दी जाये, उसी तरह यह जो दस साल का रिजर्वेशन है, इसको भी हमें भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में बीस साल के लिये कर देना चाहिये।

यह कहा गया कि जो उच्च वर्ण के लोग हैं या सवर्ण लोग हैं, उनको चुनाव लड़ने में तक्लीफ होती है और हरिजनों के लिये डबल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी के बजाय सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी होनी चाहिये, क्योंकि डबल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी में हरिजनों को चुनाव का संघटन और खर्चा कम पड़ता है और सारा भार सवर्ण मेम्बरों पर पड़ता है और उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी यह बतलाना चाहता हूँ कि यह एक तरफा मामला नहीं है। यदि हरिजनों को खर्चा और संघटन का काम कम करना पड़ता है, तो हरिजनों के बोट कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को मिलते हैं। ये जो बोट मिलते हैं, ये

हरिजनों की मदद करने से ही मिलते हैं। अभी हरिजन कमजोर हैं, इसलिये यदि हमने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया तो य कोई नुकसान की बात नहीं है। इससे सवर्ण को फायदा ही होता है। इस प्रकार हरिजनों से सवर्ण लोगों को फायदा होता है और सवर्ण लोगों से हरिजनों को फायदा होता है। तो यह जो सवाल आया था कि हरिजनों की सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूंसी कर देनी चाहिये, हरिजनों को अलग कर दिया जाये, ज्वाइंट न रखा जाये, मेरा खयाल है कि ज्वाइंट रखना ही ठीक होगा।

इसके अतिरिक्त दस साल के बजाय बीस साल करने में एक लाभ यह भी होगा कि स्वार्थी और गलत भावना पैदा करने वाले जो हरिजनों में नेता होंगे, वे भी दस-बीस साल में दुरुस्त हो जायेंगे। उनमें जो अच्छे हैं, वे कायम रहेंगे और जो खराब हैं उनको हरिजन स्वयं उतार करके अलग फेंक देंगे। इसीलिये मैं चाहता हूँ कि स्टेट्स में और सेंटर में यह रिजर्वेशन दस साल और रहना चाहिये। पार्टियों से यह काम नहीं हो सकता है। अगर आप यह उम्मीद करें कि कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या दूसरी अन्य पार्टियाँ अपनी ओर से कोई न्याय हरिजनों के साथ कर सकेंगी, तो यह शक है, बल्कि होगा यह कि मौका मिलते ही हरिजनों की सारी सीटें ये पार्टियाँ हड़प जायेंगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस अवधि को न बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आखिर इससे नुकसान क्या है? आप यह देखिये कि गांधी जी ने कैसे ऊँचे पाये पर हरिजनों को उठाया। उन्होंने कहा था कि हमने सदियों तक हरिजनों पर अत्याचार किया है। मैं हिन्दू धर्म-शास्त्रों के ऊँचे असूलों की निन्दा नहीं करना चाहता, लेकिन व्यवहार में जो पौराणिक धर्म हमारे देश में आ गया, जिसने जाति धर्म को स्थायी किया, उसके अनुसार हमने कई सदियों से हरिजनों पर अत्याचार किया। तो मैं यह

[ श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय ]

कहना चाहता हूँ कि अगर हम यह अवधि दस-बीस साल के लिये और बढ़ा देते हैं, तो इसमें हमें क्यों शिकायत होनी चाहिये । मैं और अधिक भाषण न देकर इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि इसके लिये गवर्नमेंट कोई उचित तरीका सोचे, ताकि यह अवधि ऐक्टर्ड की जा सके ।

SHRI H. N. KUNZRU: (Uttar Pradesh) : Mr. Chairman, when the Constituent Assembly passed article 334 of the Constitution it was well-understood that the disabilities from which the scheduled castes and the scheduled tribes were suffering would not be removed in 10 years. Some Members of the Assembly, therefore, moved Resolutions with the object of removing this limit of providing that Parliament should have the power to amend article 334 in the ordinary way. This amendment was not accepted by Dr. Ambedkar who was the Chairman of the Drafting Committee at that time but some observations made by him will interest hon. Members. It appears from his speech on the 25th August, 1949 that he himself was in favour of continuing the reservation of seats for the scheduled castes and the scheduled tribes for a longer period than 10 years but he pointed out that the representatives of these classes, a majority of whom belonged to the Congress Party, had themselves opposed the maintenance of this provision for a longer period than 10 years. But he made no secret of the fact that he himself thought that the period provided was not enough for the development of the scheduled castes and the scheduled tribes. He pointed out that the other classes that had enjoyed separate representation had done so for a fairly longer period before 1949. The Muslims, he pointed out, had enjoyed it practically for about 60 years and the Christians had enjoyed it for about 28 years. To suppose, therefore, that

the scheduled classes and the scheduled tribes would be able to stand on their legs in a period of 10 years seemed to him to show an inadequate understanding of their position. With regard to the scheduled tribes, he said:

"For the scheduled tribes, I am prepared to give a far longer time but all those who have spoken about the reservation to scheduled castes and scheduled tribes have been so meticulous that the thing should end by 10 years."

This makes it clear what was in the minds of even Members of the Drafting Committee when article 334 was

passed. I think, most of the 12 NoowMembers believed that this

question would be carefully looked into before the period of ten years expired and they felt almost certain that it would be extended so as to give the communities concerned the protection that article 334 was meant to give for an adequate length of time.

We have to see whether the purpose of reservation of seats has been achieved. One has only to read the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to realise that this purpose is far from having been achieved. In the matter of the provision of funds, the Central Government has been much more liberal than the State Governments. A sum of Rs. 39 crores was provided in the First Five Year Plan and I think a sum of Rs. 91 crores has been provided in the Second Five Year Plan for the development of the backward classes. But the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shows that the State Governments, generally speaking, have not taken as much interest in this question as the Central Government has. This is another reason, Sir, why we should be prepared to accept Shri Rajabhoj's Resolution.

Anyone who has any acquaintance with the state of things prevailing in

the country will, I think, be fairly prepared to admit that if the reservation of seats is discontinued, say in 1961, the progress of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will be seriously affected thereby. The Government can say, no doubt, that they are doing what they can to give scholarships to the children of these classes for their education; that they have reserved a certain number of vacancies in the public services for members of these classes and so on. But it has to be remembered that the existence of the representatives of these communities exercises a real pressure on the Government and makes all the members of this House to realise that they owe a duty to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which should be discharged as quickly and as effectively as possible. If these reservations were taken away and their number went down as a result of it, I have no doubt that the feeling of Members of all sections of this House with regard to this question will not be the same as it is now. This is another reason why I am in favour of acceptance of Shri Rajabhoj's Resolution.

There is just one more point that I wish to refer to before resuming my seat. Consider, Sir, the provisions made in Schedules Fifth and Sixth for the administration of certain tribal areas in Assam. Can any one say that the necessity for having these Schedules will end by 1960 or 1961? I am sure that these Schedules will not be deleted from the Constitution very soon. This means that the backwardness of the tribal people will continue for a long time and that it will be necessary to treat them on a special footing. It is necessary, therefore, that their special position should be recognised in the matter of reservation of seats in the legislatures also. I may refer to one thing in this connection. Tribal Advisory Committees have been provided for in the Constitution and they are to consist to the extent of 75 per cent, of the representatives of

these communities in the legislatures. It will become totally ineffective on the present basis if the reservation that is now provided in article 334 were taken away. I know that the Tribal Advisory Committees can still continue to exist. But they will not enjoy the same representative position that they do now. It is quite clear, therefore, that if we seriously mean to do the best that we can in order to improve the condition of the backward classes, including the tribal people and the members of the Scheduled Castes, it is necessary that the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes should continue for a longer period of time than the ten years period and that article 334 ought to be modified accordingly. I, therefore, wholeheartedly support the Resolution moved by my hon. friend Shri Rajabhoj.

**पंडित अल्लू राय शास्त्री (उत्तर प्रदेश) :**

सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री राजभोज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रश्न की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। अभी मेरे माननीय मित्र पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने अच्छे से अच्छे शब्दों में, मार्मिक शब्दों में, तर्कपूर्ण शब्दों में उनके प्रस्ताव का समर्थन किया है और इससे पहले श्री विजयवर्गीय ने भी उन्हीं उद्गारों के साथ इस भवन के सामने कुछ बातें कही हैं।

मैं समझता हूँ कि जिस परिस्थिति में यहां की संविधान-परिषद् बैठी थी, उसमें हमारे देश के जैसे विचारक और नेतागण बैठे थे उन्होंने परिस्थिति से विवश हो कर ही इस प्रश्न को स्वीकार किया था कि किसी न किसी प्रकार का संरक्षण इन पिछड़ी हुई जातियों को मिलना चाहिये। पिछड़ी हुई जातियां और ऊंची नामधारी जातियों के मनुष्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं। यदि किसी सम्मानित धनिक वर्ग या सत्ता-धारी वर्ग के साथ बैठ कर खाने की मेरी

[पंडित अल्लू राय शास्त्री]

इच्छा हो तो मुझे उस टेबिल पर जाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिये नहीं कि मैं अछूत हूँ बल्कि इसलिये कि मैं उस वर्ग में नहीं आता हूँ। यह तो एक अलग बात है, लेकिन कल्पना कीजिये उस व्यक्ति की जो कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है, जो कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे आदमियों को अपनी दूकान पर नौकर रख सकता है—कानपुर में इन पिछड़ी और अछूत जाति के कहलाने वाले लोगों में ऐसे व्यवसायी हैं—किन्तु वह न तो किसी के हाथ में पानी दे सकता है जिसे कि वह पी सके और न तो उसको ही कोई अपने हाथ से पानी दे सकता है जिसे कि वह स्वीकार कर सके। तो कैसी दयनीय स्थिति है। ऐसा ही सामाजिक अभिशाप गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जा कर उन बस्तियों में देखा जो कि गोरों की बस्तियों से पृथक् बस्तियाँ थीं और उन्हें वहाँ लगा कि हमारे भंगियों की जो बस्ती है उसमें रहने वालों की क्या दुर्दशा है। ऋषि दयानन्द ने दूसरे ही दृष्टिकोण से इसको देखा कि एक बड़ी पुरानी परम्परा के मानने वाले कुछ लोग अपनी ही दुर्बलता के कारण, अपने ही दृष्टि-दोष के कारण, अपने अंग न रह कर कटे जा रहे, बाहर जा रहे हैं और उनको दूसरे लोग संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह, राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न पिछले ५० वर्षों में इस देश के सामने था और उस स्थिति को देख कर ही हमें मजबूर होना पड़ा कि हम किसी न किसी प्रकार का संरक्षण इन जातियों को दें।

रैमजे मैकडानल्ड का कम्युनल एवाइडेंस चल गया होता तो पता नहीं कि ये जातियाँ कहाँ जातीं, यह देश कहाँ जाता, हमारा राष्ट्र कहाँ जाता, हमारे जातीय जीवन को कितना धक्का लगता? उससे बचने की चेष्टा गांधी जी ने की और इस देश को बचा लिया। हम 'एज ए नेशन' तड़प रहे थे

क्योंकि अंगरेजी शासन किसी तरह से देश के अन्दर तरह तरह के विभाग करके हुकूमत करना चाहता था। हिन्दू मुसलिम पैक्ट जो लखनऊ में हुआ था उससे पृथक् निर्वाचन प्रणाली यहाँ जारी हुई। स्वयं मुझे कुछ स्मरण आता है, चेम्बरलेन साहब की यह राय थी कि वह क्या एसेम्बली होगी, वह क्या विधान-सभा होगी, वह तो एक धार्मिक परिषद् होगी, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग बैठ कर विचार करेंगे, इसलिये क्यों धार्मिक दृष्टि से एक वर्गीकरण किया जाय। उससे निजात पाने की इस देश के नेताओं की चिन्ता थी। इस देश के जातीय जीवन में हर तरफ जो पृथक्ता की भावना काम कर रही थी उसे हटाने को हमारे राष्ट्रीय नेताओं को अभिलाषा थी जिससे एक राष्ट्रीयता, एक जातीयता और एक सुदृढ़ शासन यहाँ पर लाया जाय। तो इस बात की चेष्टा हो रही थी, और अगर उस चेष्टा में भी उस वर्ग को संरक्षण देने की बात धारा ३३४ के अन्तर्गत की गई तो वह परिस्थिति की विवशता थी। जातीय जीवन को बनाने के लिये यह आवश्यक था कि हम उनको स्थान दें।

"अन्नादे: संविभागः प्रजानां यथार्हतः"

प्रजा वर्ग की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार संरक्षण और प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। जो दुर्बल हैं, जो बच्चे हैं, जो स्त्रियाँ हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का संरक्षण और विशेषाधिकार दिया जाना चाहिये था, यद्यपि हमने मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लिंग-भेद से, जाति-भेद से, धर्म-भेद से किसी प्रकार की पृथक्ता बरतने का या विशेषाधिकार देने का विरोध किया है। जहाँ सामान्य नियम हमने यह माना वहाँ परिस्थिति से विवश हो कर इस बात की आवश्यकता हुई कि दस वर्ष तक उनको संरक्षण दिया जाय। संरक्षण विधान-सभाओं में और केन्द्रीय विधान निर्मात्री संगठनों में

और संस्थाओं में भी दिया गया, दस साल के लिये। अब इससे बड़ा संरक्षण कोई नहीं है। आप नौकरियों में से संरक्षण हटा लें, वहाँ पर सीधे योग्यता के आधार पर आप सर्वोत्तम में लोगों का लें तो इतनी हानि नहीं होगी। आप सब जगह से संरक्षण हटा सकते हैं, लेकिन अगर विधान-सभाओं से संरक्षण हटा जाय तो इस वर्ग में से जो नेता पैदा हो सकते हैं वे नेता पैदा नहीं हो सकेंगे और जनसम्पर्क उनका होगा ही नहीं। इन विधान-सभाओं में जो लोग होंगे वे जनता के सम्पर्क में हर पांच वर्ष बाद आते हैं। उस समय वे जनता के बीच जाकर बोलते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार हमें इस वर्ग में से नेता मिलते हैं। यहाँ नहीं कि हम उनके साथ कोई दया दिखा रहे हैं। बल्कि हम अपने ऊपर न्याय कर रहे हैं कि अपने जातीय जीवन में उन पिछड़े हुए वर्गों में से नेतृत्व पैदा करते हैं। वे जनता के सामने जाते हैं, बोलते हैं, उनको राष्ट्रीय प्रश्नों के विषय में जागरूक बनाते हैं।

एक बात और है। हम चाहें तो हम यहाँ उनको नामजदगी से भी उतना ही प्रतिनिधित्व, २५ फी. सदा का जगह ३० फी. सदा, दे सकते हैं। लेकिन वह हानिकारक होगा क्योंकि तब सत्ताधारी दल, जो शासन चलाता होगा, अपने आदिमियों को लाकर यहाँ बैठा देगा। जब हम चुनाव की प्रणाली में उनको डालते हैं तब लाभ यह होता है कि हर दल के लोग अपने आदिमियों को खड़ा करते हैं इसदस्यीय चुनाव क्षेत्र में या एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र में। उस समय एक दल ने अनुक व्यक्ति 'ए' को खड़ा किया हरिजन सोट के लिये, सिड्गुल्ड कास्ट को सोट के लिये, दूसरे राजनैतिक दल ने 'बी' को खड़ा किया, तौसरे ने 'सी' को खड़ा किया और चौथे ने 'डी' को खड़ा किया। इस प्रकार एक ही वक्त में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चार नेता प्रकट हो जाते हैं। लेकिन

नामिनेशन से एक ही व्यक्ति के खड़ा होने का प्रश्न होगा। इसलिये निर्वाचन प्रणाली के आधार पर इस प्रकार का संरक्षण इन जातियों के जीवन को मजबूत तो बनाता ही है, साथ ही राष्ट्रीय जीवन को भी मजबूत बनाता है क्योंकि हम अच्छे आदिमियों को खोज कर निकालते हैं। इस प्रकार हम धरती के नीचे पड़े हुए फूलों को धूल में से निकालते हैं और उन फूलों का माला भारत माता के गले में पहनाते हैं। इसलिये इस प्रकार की प्रणाली को अगर हम छोड़ दें तो हम उनको तबाह कर देंगे, बल्कि उनके पूरे जातीय जीवन को तबाह कर देंगे क्योंकि जातीय जीवन में जितने विचारक पैदा होंगे, जितने सुचारक, पथप्रदर्शक पैदा होंगे, जितने ही जनता के सामने आ कर नेतृत्व देने वाले पैदा होंगे, जितने ही नेता पैदा होंगे उतना ही देश का सम्मान होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि अभी कुछ न कुछ दिन तक संरक्षण जारी रखना चाहिये।

जब सन् १९३७ में इलेक्शन हुए थे उस जमाने में हमने देखा कि कांग्रेस के टिकट पर आने वाले लोग किस किस क्षेत्र में थे और आज कौन लोग हैं, हम देख रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं वह यह है कि सत्ताधारी धारे धारे प्रकट हो रहे हैं, चले आ रहे हैं। जितने पास पैसा नहीं है, वे इलोमिनेट हो जायेंगे, वे कहीं टिकने वाले नहीं हैं, वे कभी स्वतंत्र रूप से आ नहीं सकेंगे और कभी उनको स्थान नहीं मिल सकता क्योंकि धन उनके पास नहीं है, संघर्ष में वे पड़ नहीं सकेंगे। जब हम इस वर्ग के लोगों को संरक्षण देते हैं तो इन्हें संघर्ष में पड़ना होगा और विवश हो कर इलेक्टोरेट के पास चुने जाने के लिये जाना ही होगा और इसमें चुनाव की प्रणाली से ही उनको आना चाहिये, नामजदगी की प्रणाली से नहीं आना चाहिये, ताकि जनसम्पर्क में इन्हें रहना पड़े। इसलिये आवश्यक

[पंडित अत्तू राय शास्त्री]

है कि यह संरक्षण कुछ दिन और कायम रखा जाये। इतने दिन कायम रखा जाये जितने दिन अनिवार्य हो, अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। एक दिन अधिक नहीं और एक दिन कम नहीं। मैं समझता हूँ, दस वर्ष एक परीक्षा काल था। इस दस वर्ष की अवधि में इस वर्ग से जाने वाले प्रतिनिधियों ने जो सेवा की है, जिन भावों का प्रकाशन किया है और देश के साथ जो वफादारी बरती है वह इस बात के लिये उनको पारपत्र प्रमाणित करता है कि फिर से उनको अवसर दिया जाये। मामूली दाँड़ के लिये अगर कोई कमजोर लड़का हंता है तो उसको दस गज आगे दे देता है। हर 'बाक आफ़ लाइफ़' में कमजोरों को ग्रेस मार्क दिया जाता है। इस किस्म की बातें पाई जाती हैं। तो जब पृथक्ता की भावना बढ़ती है तब हम अलग अलग खड़े हो जाते हैं, अलग अलग दिखनाई पड़ते हैं। लेकिन हमें सारी स्थिति को सामने करना चाहिये—जो परिस्थिति की दुशवारी है, जो परिस्थिति की विवशता है। 'बो मस्ट फेस दी फैक्ट्स' वाला लाजपतराय जो का यह वाक्य मुझे नहीं भूलता है कि जो वस्तु-स्थिति है उसको आदर्शों और कल्पनाओं के आगे आंख मूंद कर देखना नहीं चाहिये। हमको परिस्थितियों को देख कर, उनके अनुसार ही काम करना चाहिये, उनके मुताबिक काम करना चाहिये। यह पिछड़ा हुआ वर्ग हमारे देश को एक धराहर है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के ये तन्हे नन्हें बच्चे अच्छा रत्न पैदा कर सकते हैं अगर हम उन्हें अवसर दें। अवसर और कैसे दिया जा सकता है? अगर उसका दूसरा तरीका हो तो बता دیجो। अगर आप उनको टिकट भे दें और खड़ा भी कर दें तब भी दूजरे लोग स्वतंत्र रूप से खड़े हो कर उन्हें हरा देंगे। हम प्रजातंत्र की प्रणाली से इंवेक्शन की पद्धति को हटाना नहीं चाहें।

और अगर नहीं हटाना चाहते हैं, अगर उनको इसके द्वारा लाना चाहें हैं तो नामजदगो से नहीं, निर्वाचन प्रणाली से ही ला सकते हैं। उनको संरक्षण देना ही होगा ताकि इन्हें से नेता पैदा हों। वे लोग कुछ इस तरीके से जीवन बितायें कि उनके हाथ में चार पैसे भाँ हों, आने वाले जनाने में वे स्वतंत्र संघर्ष में पड़ सकें, अपने प्रतिद्वंद्वियों से लोहा ले सकें और अपने को 'एसर्ट' कर सकें। इसके बाद वे अपने जातीय जीवन के प्रश्नों पर विचार करें उसको उन्नत बनाने का काम करें।

यहाँ पर राजभोज जी ने जो प्रस्ताव रखा है—चाहे दस साल के संरक्षण को बीस साल न करें, १५ साल ही करें, या बीस साल का पच्चीस साल करें, इस प्रश्न पर गवर्नमेंट विचार कर ले जो भी वह ठक समझे—सरकार का उत्तर क्या होगा उसको सुन कर ही हम उसको जान सकते हैं। लेकिन मैं जरूर राजभोज जी से यह अनुरोध करूँगा कि जिस तरह की सरकार आज है, हमारे इस महकमे को चलाने वाले पंत जो उसमें बँटे हैं, उसमें नेतृत्व इस प्रकार का हो जो सम्भावना से प्रेरित हो कर काम करे। सरकार की तरफ से जो बातें कही जाएंगी उनको सुन कर राजभोज जी आवश्यकतानुसार अपने प्रस्ताव में संशोधन भी कर लें। लेकिन मैं जो अपना उद्गार प्रकट करना चाहता हूँ वह यह है कि यह संरक्षण समाप्त किये जाने लायक अभी नहीं है, इसको बढ़ाना आवश्यक है और अनिवार्य है।

श्री. बे.को.म्बन नारायण (मुम्बई) :  
आदरणीय सभापति जी, प्रस्तावक मित्र ने जिन भावनाओं के साथ इस प्रस्ताव को पेश किया, उन भावनाओं के साथ मेरी सहानुभूति है।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का जो व्योरा यहाँ रखा गया, उसमें भी बहुत कुछ सचाई है। मेरे भाई अभिभोज ने भी जिस दुःख के साथ बहुत सी बातें यहाँ कही हैं वे भी समय में आ सकती हैं। फिर जो विशेष जोश उन्होंने दिखाया उसका कारण भी वे दिखा नहीं सके।

श्री रामेश्वर अभिभोज : दिग्गता कहाँ ही नहीं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : वे दिखा नहीं सके। खैर, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उस पर ठंडे दिम से विचार करना चाहिये, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने मेमरेट इन्स्टोरेट और रिजर्वेशन आफ साट्स का तत्त्वतः शुरू से ही विरोध किया है। हम लोगों ने कांस्टिट्यूट कोम्प्रेजी के वक्त इसको एक नौसरी ईवल, आपतिप्रस्त-जरूरी मान कर यही पसंद किया कि रिजर्वेशन की बात को दस वर्षों के लिये स्वीकार कर लेना चाहिये। इसे हमने इष्ट आपति के तौर पर माना। अब हमें यह सोचना चाहिये कि इस आपति को कितने दिनों तक रखना चाहिये, और कितने दिनों तक इसको चलाना आवश्यक है। आपने अखबारों में देखा होगा कि हमारे बैकवर्ड क्लासेज के जो कमिश्नर हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी हरिजनों की सेवा में लगा दी है, उन्होंने अपने विचार इस विषय में प्रकट किये हैं। मुझे अखबार से पता हुआ कि उन्होंने यह कहा कि आदिम जातियों के लिये तो यह सोचा जा सकता है कि उनके लिये रिजर्वेशन की जो भियाद है उसे बढ़ा दिया जाय, परन्तु हरिजनों के लिये ऐसा कहना मुश्किल है और इस प्रश्न को दुबारा सोचना चाहिये। तो जब एक मनोनीत अधिकारी ऐसी बात कहता है तब हमें यह सोचना चाहिये और

देखना चाहिये कि देश में, आज की हालत में, कहां तक और कब तक यह रिजर्वेशन आवश्यक है और उसके बाद हमें कोई बात तय करनी चाहिये। हालांकि उन्होंने एक तरह से विरोध ही दर्शाया है, परन्तु साथ ही इस बात को कहा है, इस बात को प्रकट किया है कि हमें इस बात पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री पा० ना० राजभोज : विरोध तो नहीं किया है।

श्री देवकीनन्दन नारायण : रिजर्वेशन आफ साट्स के साथ हरिजनों की सुविधाओं का या दिक्कतों का, कोई खास सोचा सम्बन्ध है, ऐसा मैं नहीं मानता। महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने असुश्यता निवारण के लिये गत चालीस वर्षों से जो कार्य किया, वह इतना जबरदस्त कार्य था कि वह किसी कानून से कभी नहीं हो सकता। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमने अपने संविधान में यह स्पष्ट कर दिया कि असुश्यता मानना एक गुनाह है और इसके साथ साथ हरिजनों की जो डिसएबिलिटीज हैं उनको निकालने के लिये हर एक स्टेट में कानून पास किये गये। एक नहीं अनेक कानून पास किये और कानून पास करने के बाद सारे देश में उन पर बहुत कुछ अमल भी हो रहा है। यदि मैं नश्रतापूर्वक यह कहूँ कि हरिजनों का सेवा कार्य जितना सवर्ण भाइयों ने, कार्यकर्त्ताओं ने किया है और कर रहे हैं, मुझे शक है कि उस परिमाण में हमारे हरिजन भाई भी कर रहे हैं या नहीं।

श्री तिशोरी राम : यह गलत कह रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन नारायण : गलत हो सकता है। पर मेरा यह विश्वास है कि आज सवर्ण भाई और उनकी संस्थाएँ हरिजन सेवा के लिये, उनकी दिक्कतों को कम करने के लिये जितना कार्य कर रही हैं उतना कार्य हरिजन कार्यकर्त्ता कर रहे हैं ऐसा म-



[श्री देवकीनन्दन नारायण]  
नहीं मानता । यह मेरा विश्वास है और  
अनुभव है ।

डा० डब्ल्यू एस० बालिगे (मुम्बई) :  
यह उनका काम नहीं है ।

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैं मानता हूँ, इसलिये मैं कह रहा हूँ । जो बात मैं कह रहा हूँ किसी मतलब से कह रहा हूँ । मेरे कहने का मतलब यही है कि हरिजनों की दिक्कत कम करने, हरिजनों की अशुविधा कम करने हरिजनों की अस्पृश्यता दूर करने का काम सबर्णों का है । सबर्णों के लिये यह काम करना उनका धर्म है और इस बात को हमने विधान में भी मान लिया है । चालीस वर्ष के काम से हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यह हमारा धर्म है, इसे हमें करना चाहिये । हमारे डा० कुंजरू साहब ने जो यह कहा कि हरिजनों को रिजर्वेशन आफ सीट्स दे कर और यहां लाकर बैठाने से हम पर प्रेशर पड़ता है और हम हरिजनों के लिये काम करने लगते हैं नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आई । यह हमारा आज तक का अनुभव कभी नहीं रहा । मेरे कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स का जो सवाल है, उसको हमें स्वतंत्र दृष्टि से देखना चाहिये ।

SHRI H. N. KUNZRU: May I ask my hon. friend whether he realises what the effect of the withdrawal or reservation of seats, at least on the tribal people, will be ? Can any Government seriously propose to withdraw this right, say, from the tribal people in Assam? The whole State will be in a blaze if any such unwise thing were done.

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने अभी तक एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि 'ड्राइवल पीपुल' को जो रिजर्वेशन दिया हुआ

है वह खत्म कर दिया जाय ।  
I have not spoken a single word about it.

SHRI H. N. KUNZRTT: Think of the effect of the withdrawal of the right that we are discussing even from, the scheduled castes in the country.

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने अभी तक यह भी नहीं कहा कि डिड्युल्ड कास्ट को रिजर्वेशन न दिया जाये । मैं तो यह कह रहा हूँ कि इस सवाल को गंभीरता से सोचना चाहिये । दस वर्षों में जो कुछ काम हुआ है, जो हालत पैदा हुई है, जो पोलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है, जो सामाजिक सिचुएशन पैदा हुई है, उन तमाम बातों को सोच समझकर इस बात का फैसला करना चाहिये कि आगे दस वर्ष के लिए इस तरह की सुविधा दी जानी चाहिये या नहीं । मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूँ । आप कृपा करके गलतफहमी पैदा न करें । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन कारणों का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, वे कारण मेरी निगाह में काफी नहीं हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज देश में चारों तरफ सेपरेटिस्ट भावना बढ़ रही है । हिन्दुस्तान में हजारों बैकवर्ड जातियां हैं, जो उतने ही बैकवर्ड हैं, जितने कि हमारे हरिजन भाई ।

श्री किशोरी राम : क्या इस तरह की भावना अनुसूचित जातियों में भी है ?

श्री देवकीनन्दन नारायण : मैंने यह कभी नहीं कहा कि अनुसूचित जातियों में है कि नहीं । मैं तो यह कहता हूँ कि यह भावना सारे देश में बढ़ रही है । ऐसी हजारों जातियां हैं जिनमें सेपरेटिस्ट भावना मौजूद है । यदि हम इस सेपरेटिस्ट भावना को बढ़ने देंगे और हरिजनों को रिजर्वेशन आफ सीट्स देने के सवाल पर ठीक तरह से विचार नहीं करेंगे तो देश में जो छोटी छोटी



पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड जातियां हैं, वे भी इस मार्ग को करने में पीछे न रहेंगे। मैं आप से कहता हूँ कि आप मुसलमानों को ले लीजिये। एक बहुत बड़ा सवाल उनकी ओर से इस देश में पैदा होने का डर है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हमारे शहर की म्युनिसिपैल्टी में लोक संस्था के परिमाण में मुसलमानों को छः जगहें मिलती थीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पांच जगहें मिलती थीं। लेकिन जब से रिजर्वेशन का सवाल हटा लिया गया है तब से उनको एक भी सीट नहीं मिल रही है। मैं अपने प्रांत की बात कह रहा हूँ। आज आप जानते हैं कि किस तरह से पोलिटिकल पार्टीज का काम होता है, किस तरह से पोलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। उसका नतीजा यह हुआ है कि whole Harijan community is divided into sub-castes. उनमें जो छोटी छोटी अलग अलग जातियां हैं उन्हें हमारी पार्टीज कंपचर करने की कोशिश करती हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि the whole Harijan community is divided.

**श्री किशोरी राम :** यह तो वहां के कांग्रेसियों की वजह से हुआ है।

**श्री देशकानन्दन नारायण :** मैं तो सारी पोलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रहा हूँ। आपको शायद कांग्रेस से दुश्मनी पैदा ही गई है।

यह भी यहां कहा गया है कि यह रिजर्वेशन समाप्त हो जायगा तो शायद यहां कोई हरिजन चुन कर नहीं आ सकेगा। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। मैं अपने विचार भी कह दूँ कि गत १९५७ के इलेक्शन में हमारे प्रांत से जनरल सीट्स पर पार्लियामेंट में हरिजन चुन कर आये हैं। (Interruptions.) मध्य प्रदेश से भी चुन कर आये हैं। तो यह कहना कि यदि रिजर्व सीट्स न दी जायें तो

जनरल सीट्स से हरिजन चुन कर आ नहीं सकते, यह बात ठीक नहीं है। लोग चुन कर आयेंगे। चुन कर आना बहुत सी बातों पर निर्भर होता है, बहुत से कारणों पर निर्भर है।

मेरे भाई अलगू राय शास्त्री जी यहां तक पहुंच गये कि जो स्कालरशिप और सर्विसेज का रिजर्वेशन है वह भले ही न रहे। मैं इस मत का हूँ कि जब तक बैकवर्ड्स हैं तब तक स्कालरशिप्स दिये जायें, सर्विसेज में संरक्षण दिया जाये और सारे प्रोटेक्शंस दिये जायें, परन्तु इन तमाम प्रोटेक्शंस का रिजर्वेशन आफ सर्विसेज के साथ कोई सम्बन्ध है, ऐसा मैं नहीं मानता। पार्लियामेंट और असेम्बली में रिजर्वेशन एक अलग बात है, और जो बैकवर्ड हैं उनको स्कालरशिप देना और सर्विसेज में लेना यह अलग बात है। इसलिए यदि आप ऐसा कहेंगे कि चाहे सर्विसेज में प्रोटेक्शन न दिया जाय लेकिन यह रिजर्वेशन बना रहे, तो सारे हरिजन आपको गालियां देंगे और आपके दुश्मन बन जायेंगे। क्योंकि स्कालरशिप और सर्विसेज न मिलने से हजारों व लाखों हरिजनों का नुकसान होगा और इस रिजर्वेशन के रहने से दस, बीस, पचास आदमियों का ही नुकसान होगा।

(Time bell rings.)

घंटी बज गई।

**श्री उपसभापति :** एक मिनट है।

**श्री देशकानन्दन नारायण :** मैं फिर यह कहूंगा कि कोई यह गलतफहमी न कर ले कि मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूँ। मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनमें से एक हूँ जिसने १९१९ से हरिजनों की सेवा की है।

**श्री रामेश्वर आगनभोज :** ठीकर बप्पा के सेवक मानते हैं।

**श्री देशकानन्दन नारायण :** धन्यवाद। १९२३ में मेरे शहर में जो अखिल-भारतीय

[श्री देवकीनन्दन नारायण]

वर्णाश्रम परिषद् हुई थी उसके अध्यक्ष हमारे वैष्णव धर्म के आचार्य थे। सब से पहले उस परिषद् में हरिजनों को ले जाने के लिए हम लोगों को लाठियाँ खानी पड़ी थीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई यह गलतफहमी न कर ले कि मैं इस प्रश्न में किसी से पीछे हूँ। मेरा कहना यह है कि हरिजनों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर कीजिये, उनको अपने पास लाइये, उनको जितनी सुविधायें आप दे सकते हैं दीजिए, परन्तु यह जो पोलिटिकल सवाल है इसको अलग, बहुत से पहलुओं से, आपको देखना होगा। आज देश में जो सेप्रेटिस्ट मेंटैलिटी बढ़ रही है, अलग अलग फ़िरकाबन्दी बढ़ रही है, अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप बन रहे हैं, इन सबको देखते हुये कहां तक रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना ठीक होगा, यह प्रथम सोचा जाय। इसके लिये एक कमेटी कागम की जाय और वह कमेटी देखे भाले और सोचे फिर इस बात का निश्चय किया जाय, यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

SHRI N. C. SEKHAR (Kerala): Mr. Deputy our Government has been preparing Chairman, I rise to offer our full support to periodically lists of Scheduled Castes and the Resolution moved by Mr. Rajabhoj. Our Scheduled Tribes with a view to provide ample esteemed friend Dr. Kunzru has very clearly protection and also amenities for their social and argued to justify the demand for extending the economic development. Now the demand is period of reservation of seats in Parliament there. This period prescribed according to an and State Legislatures provided for the mem- article of the Constitution would not be suffi- bers of the Scheduled Castes and Scheduled cient. It will not sufficiently help them to Tribes. achieve the end within the prescribed period.

Sir, it is a surprise to me that certain extended, that is, the amenities for the Members came forward to oppose this Scheduled Castes and Scheduled Resolution on several pleas, and one of such pleas is that this demand for reservation will lead to separatism. You know, Sir, I come from a State where there was a strong movement for separate reservation of seats in the local Legislature for certain communities who

*Seats for Scheduled*

suffered under certain dominant communities. That was a strong movement. It was some 25 years ago. One community dominated the political field and they captured all the seats in the Legislature relegating all the other communities to the background. Then those communities jointly started a movement not only for seats in the Legislature but also for seats in the services. Then the cry arose from the members of the dominant community that here and there certain-people who were there to organise a separatist movement would spell ruin to our country. But in fact that movement succeeded and they won reservation of seats, particularly reservation of seats in the Legislature. i But, by and by after several years that separatist outlook had gone. They had developed socially, educationally and financially as a consequence of which that separatist outlook was not there. Now members of those communities can contest seats freely, not on the basis of reservation, but as members of any other communities. They can get easily elected to the Legislature. Now there is no cry. Why I illustrate this is to show that this demand for reservation will not have led to separatism. It is not a movement out of separatist outlook or mentality but out of legitimate demands that they should have their place in the body politic, among other communities^ It is because of this view that our Constitution has provided protection to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and to serve that purpose

Therefore the cry is that that period should be

Tribes should be extended to 20 years, i That demand is there and it is a strong demand. Very recently we had a conference in the Central Hall of Parliament House with States Minister representing the welfare activities in the respective States in which the same demand was put forward, and it was a legitimate demand. That extension has to be granted by the Central Government and in view of that it is also legitimate and just to extend the period of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the local Legislatures as well as Parliament. Sir, allowing this reservation for some further period will not lead to separatism. Rather it will provide some political education to the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to work hard and depend on themselves instead of depending on the *Savarna* members.

Well, Sir, I could not exactly follow what our friend, Shri Deokinandan Narayan, said. But what I understood him to say is that the responsibility of seeing that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people are uplifted rests with the *Savarna* people. Of course, the members of the *Savarna* community have helped them for the last 37 years. I remember the day when I joined this movement in 1921 when I was 13 years old. In those days we were trying to sit along with the Harijan boys, to spin *clxarfcfias* and to produce yarn together, because that was the first type of work which we started to bring up the Harijan boys with a view to do away with untouchability and unapproachability. Since then, of course, it was the *Savarna* Hindus who took the initiative to work among the Haxijans with a view to bring them up along with the other developed communities. Now it is the duty of the Harijan friends also to take the responsibility to work among them and also to help them in taking to industrial and other constructive activities, so that their men may also come up along with the

other communities. I know, it will take some generations to achieve that objective. I do not think this objective can be fulfilled within ten or fifteen years. It will take more than that no doubt. I know that some communities in our part of the country were suffering and it took them generations to become equal to the other developed communities. So, Sir, all sorts of facilities should be provided and should continue to be provided so that they may also come up to the level of other developed communities. With that end in view, it is only just and proper to extend the period of this reservation. If there is no reservation, I can vouch that no Scheduled Caste member or no Scheduled Tribe member can be returned to any local Legislature or to Parliament. I know that unless there is reservation . . .

DR. W. S. BARLINGAY: They have actually come in Parliament.

SHRI N. C. SEKHAR: That is because the people at the helm of affairs are compelled to select them as candidates.

DR. W. S. BARLINGAY: They came in spite of the Congress Party . . .

SHRI N. C. SEKHAR: Of course, that was so only where they had some influence. Anyway, I will come to that point. It may be that they worked not only for the Harijan and Scheduled Caste people, but they worked for the people as a whole in the national interest in that area. In that case, certainly the people of other communities would vote for them. I do not say that all parties are like that. Even among the political parties it is not that these Scheduled Caste people are in the leadership. They are people in whom these people have no sufficient confidence. They are there because they were selected on the basis of reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. And that is why, Sir, they are insisting upon continuing this reservation

IShri N. C. Sekhar.] so that a sufficient number of them in proportion to their community population, could be returned to the local Legislatures as well as to Parliament. Other members are selected in certain other areas, but that is a rare phenomenon. And unless some reservation is provided, I am sure that the number of Harijan members who are now seen in the Legislatures will not be returned because it will be very difficult for them to be selected for that purpose. Because there is reservation, we are bound to find out some Harijan *members or some* Scheduled Caste members or some tribal men to contest for election, for example, in Assam, Orissa, Bihar and in certain other places like Santhal etc. Unless there is reservation, such tribal people cannot be returned. On the other hand, the other leaders, in the name of these tribal people and Scheduled Caste people, will go and contest and get themselves returned to the Legislatures. So, Sir, in the given situation in our country it is necessary to extend this period so that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes may enjoy their legitimate right of being returned to their respective Legislatures. Sir, with that end in view, this demand is quite just and justified, and the Government and this House should see their way to accept it, unless, of course, the mover withdraws it. So, I support this Resolution.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I should like to express my very strong sympathy with the Resolution which has been moved by Mr. Raja-bhoj. I think the question of extending the period deserves to be considered by us in a very sympathetic spirit. Indeed, speaking for myself, I would extend that period. Now it is vastly to the credit of our Constitution-makers, of our founding fathers, that they did not approach the task of Constitution-making in a

*doctrinaire* spirit. They approach the task in a realistic spirit. They knew that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes had suffered a very great deal in the past. They knew that they needed protection, and they knew that effective protection could be secured for them by enabling them to share political power. It is not enough for you to employ a few depressed class people or Scheduled Caste people in your services. It is not enough for you to give them educational scholarships. It is further necessary that they should be made to feel that they are partners in the great undertaking of governing this country. Therefore, under article 334 it was laid down that there would be reservation for them for a period of ten years. There is nothing sacred about that period. There is nothing sacrosanct about that period, and the feeling among the Scheduled Castes is that that period should be extended. We have not only to think of the Scheduled Castes, but we have also to think of the Scheduled Tribes. We are not yet out of the woods so far as the tribal areas are concerned. With a great deal of effort on our part, and with wise statesmanship on our part, the Kohima Convention was arrived at, and that has generated a feeling among the Scheduled Tribes that we mean well by them, but they have got to be integrated emotionally with this country. Now, how are we going to emotionally integrate these tribal people, these Scheduled Caste people and these Scheduled Tribe people? We cannot do it by merely lecturing to them on national unity. Nations have never achieved unity by lectures on national unity. We need, in concrete life, to give them a feeling that we mean to do justice by them. Justice must not only be done, but must also appear to be done, and it is for that reason, I think that this problem of continuing this reservation should be viewed by us in a large-hearted and sympathetic spirit—because it is only large-heartedness which will enable us to preserve and strengthen our national unity. Any bookish approach

will not help us to solve our problems. You can consult many authorities; they no doubt say that for working democracy there must be no reservation of seats for any community, because if you have any reservation, you introduce communalism, but do not forget that here you have a joint electorate, and a joint electorate preserves national unity. The member elected will be answerable to a common electorate. Therefore, this is something which must not be forgotten by us.

Another point is this: I rather like these multi-member constituencies. You must not forget that the Scheduled Castes are economically backward; they have not the finances to run a Parliamentary election or an election to the Vidhan Sabhas in the country. If they are associated with a non-scheduled caste candidate . . .

DR. W. S. BARLINGAY: That applies even to municipal elections.

SHRI P. N. SAPRU: Yes, it applies to municipal elections even. The candidate contributes something, the political party contributes something to the election expenses, and it becomes possible for him to face the electorate. If you do away with multi-member constituencies and have single-member constituencies, then it may be financially impossible for them to approach this vast electorate. You cannot depend upon political parties to nominate the requisite number of scheduled caste candidates for election to Parliament or to the Vidhan Sabhas. To do so would be to impose an impossible burden on political parties. You know, that there are groups in political parties, that there are parties within political parties, and the question of representation which is to be given to the Scheduled Castes or Tribes will get mixed up with party politics of the parties nominating them. I think, it is therefore, undesirable from that larger point of view to deny them some reservation for some time. Well, we had hoped that ten years would prove

a sufficient period, but from what I can see, that period is not sufficient, and the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has suggested that that period should be extended for the Tribes. You cannot extend that period for the Tribes without extending it for the Scheduled Castes as well, for to extend that period you will have to modify or change article 334 of the Constitution, and if the Constitution is to be amended, then you must amend it so as to satisfy the demands of both the Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Whether the period should be 15 years or 20 years, I cannot say. I think that a period of twenty years is not too large. A twenty year period would mean extending the concession of reservation by another ten years. Surely in these ten years we would have been able to carry through the Second Five Year Plan, we would have been able to carry through the Third Five Year Plan, and we shall be probably in the midst of the Fourth Five Year Plan, and during that period it is almost certain that they will advance economically, they will advance educationally, and they will be able to stand on their own feet. Once a community begins to feel that it can do away with crutches, I do not think it is likely to stick to them. After a time the community itself will begin to feel that the crutches are a drag on its progress. Therefore, generate among the Scheduled Castes the feeling that their best safeguard is their ability to stand on their own legs, and help them to do so during this period of ten or twenty years, and if you are fair to them, I am certain that they will be loyal to the country, they will be attached to the country, because let us not forget that they are flesh of our flesh, bones of our bones.

Mr. Deputy Chairman, I will tell you an incident which came to my knowledge. My wife is interested in a scheduled caste institution, and she takes a good deal of interest in it, which is located in our compound.

[Shri P. N. Sapru.] She attends invariably their annual function, and speeches were made in an annual function by some scheduled caste teachers which were of a bitter character against Brahmins. My friend, Mr. Agnibhoj, too made an attack against Brahmins.

SHRI R. U. AGNIBHOJ: Rightly or wrongly?

SHRI P. N. SAPRU: Rightly or wrongly, I cannot say. I do not think that you can ever conquer hate by hate. She came back after that meeting in a very distressed state of mind. "See what I have been doing to them so far, and yet they are so bitter." I asked her to give up that attitude. For several centuries we have been treating these classes badly. Their subconscious mind revolts against us, and if they say something, let us put it down to that. It is a process of catharsis, as psycho-analysts would say, in their case, and perhaps without this they will not be able to reconstruct their personalities. The point that I want to stress is that it is important, it is vital, it is in the national interests that this problem should be viewed by Government in a large-hearted spirit. Presided over as the Home Ministry is by our eminent leader, Pandit Govind Ballabh Pant—and we have his spokesman here in the person of our esteemed lady Deputy Minister, Mrs. Alva—I am certain that this problem will be viewed by the Home Ministry in a large-hearted spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

DR. W. S. BARLINGAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have heard with great interest the speeches on this Resolution which have been delivered in this House. I am sorry to say, though I say so with great respect, that several speakers have really missed the main point of the Resolution. This Resolution has got a very limited scope. The Resolution reads:

"That this House is of opinion that the period of reservation of seats in Parliament and State Legislatures . . ."

We are not talking here, so far as the Resolution is concerned, of untouchability generally. Because so far as the question of untouchability is concerned, I don't suppose there is any single person in this House who has the slightest sympathy with untouchability. But the point of the Resolution is and so far as the mover is concerned, all that he wants, is that article 334 of the Constitution should be kept alive for another period of 10 years. That is to say, so far as the representation in Parliament and State Legislatures is concerned, that separate representation should continue for another period of 10 years. Then the other part is—and that also is a very important part—the mover says that this should be extended only from 10 to 20 years. He does not say that this should be extended permanently. Now, therefore, the only point and the only criterion on which we should vote in favour or against this Resolution is whether there has been any change in the circumstances which prevailed at the time article 334 of the Constitution was passed, whether those circumstances, which several leaders and great leaders too, of public opinion in those days considered and arrived at the conclusion that article 334 was the proper remedy for the situation as it then existed—whether those circumstances have changed in any manner. The question is whether that situation does or does not continue till today. If that situation does con-

tinue, then obviously there is no objection to extending the period of 10 years to 20 years. As Shri Sapru quite rightly said, there is nothing sacrosanct or sacred about the period of 10 years. The 10 years period could as well be 20 years or 30 years. Therefore, the main question that should exercise the minds of speakers here is whether those circumstances which existed at the time of the passing of the article 334 of the Constitution still exist today or they don't exist. If your case is that they don't exist, don't extend the period but if the case is that they do, that those circumstances do exist, then I suppose the hon. mover of the Resolution has certainly made out a good case for his Resolution. When you put the matter in this way, I am sure you would agree that during the last 10 years, let us say from 1946, from the time we got our Independence let us say,—and I don't really think that our society has learnt the lesson it ought to have from the fact of untouchability in our society. I have had personal experience, I have moved in the villages myself, if I may say so, I myself at some period of time, was in charge of this particular portfolio in the old Madhya Pradesh and I know what difficulties Harijans have to undergo in our society. I need not repeat all that here because I know, everyone in this House is sympathetic towards the Harijans. On the other hand, it need not be forgotten that there is a good deal in the point of view that was urged by my friend Shri Deokinandan Narayan. There is a great danger in having separate representation say for Muhammadans or Harijans or scheduled castes. As a matter of fact all this is quite contrary to the spirit not only of the Constitution but to the spirit of democracy itself. We don't want any reservation for anybody as a matter of fact but then, the point is, since we, or the Constitution-framers in their wisdom found it necessary to enact this particular piece of legislation, this particular article of the Constitution, the point now is whether

those circumstances have changed and I submit, with all respect to the House and to yourself, that those circumstances have not materially changed.

Shri Narayan made a great point and that shows that the matter is not really as simple as it looks. After all if we give reservation not only to scheduled castes but to the scheduled tribes also, it appears to be an arguable case that all other minorities including the Muslims should get separate representation and once you give separate representation to separate communities, they get, so to speak, vested interest in the whole thing. Instead of trying to do away with these privileges which we give them, they insist on those privileges and they see to it that those privileges do not vanish from our society. As a matter of fact, the object of all these privileges is merely to make up for the handicap—social handicaps—that they have in our society but then our misfortune is that as soon as we begin to do it, as soon as we try to do away with this handicap, that becomes a sort of privilege that becomes a sort of vested interest and people begin to stick to it instead of trying to do away with it. That is a great danger to which my friend Shri Narayan pointed and in so far as he made out this point, he was quite right. But then I believe as I said in the very beginning this particular Resolution has got a very limited scope. It only says that so far as the Parliament and the State Legislatures are concerned, the period of 10 years under article 334 of the Constitution may be enhanced to 20 years and I don't see that there is any logical objection to this particular proposal made by the hon. mover.

श्री ना० र० मल्हानी (नाम-निर्देशित):  
उपसभापति जी, जो मैं ज्यादा करके  
बोलता हूँ जो ज़रा जोर से बोलता हूँ  
लेकिन अभी ज़रा दब करके बोलना पड़  
रहा है क्योंकि हो सकता है कि जो

[श्री ना० र० मल्काना]

मैं कहूँ उसमें कुछ गलतफ़हमी दूर न हो, शायद गलतफ़हमी ज्यादा हो, यह हो सकता है। लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो मेरे मन में है वह रखूँ चाहूँ गलतफ़हमी बढ़े या कम हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खयाल में लोगों को वाक़िफ़ करूँ कि मेरा खयाल क्या है। मेरे मन में आता है कि मैं इसका विरोध तो कभी कर नहीं सकता। मेरा मन नहीं है कि मैं विरोध करूँ। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि मैं समर्थन करता हूँ तो मैं खुद ज़रा रुक जाता हूँ और यह सोचता हूँ कि क्या समझ कर समर्थन करता हूँ। इसका समर्थन करके किसी को खुश तो नहीं कर रहा हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ।

यह जो हमारे भाई हैं, जिनको हरिजन कहा जाता है, उनके लिए यह रेजोल्यूशन चैलेंज है, चुनौती है। मैं यह भी नहीं कहता कि यह चुनौती हरिजनों को है, या मो-काल्ड कास्ट-हिन्दुओं को है। यह चुनौती हिन्दू मोसाइटी को है। मुझे यह सुन कर दुःख होता है कि तुमने यह नहीं किया, तुम यह करो। यह खयाल करना कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम यह करो, मेरे खयाल में यह गलत चीज़ है। पहली बात यह है कि मैं सोचूँ कि मैं क्यों नहीं इसका समर्थन कर सकता। मुझ को लगता है कि जो यह मांग करते हैं उसमें कुछ वजूद है, कुछ हस्ती है, कुछ चीज़ है। हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया, हमने अपने फ़र्ज की अदायगी नहीं की। मैं कह सकता हूँ कि नहीं की है। लेकिन मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम इस फ़र्ज से अब कुछ कांशस हो गये हैं। समझते हैं कि यह हमारा फ़र्ज है। पहले हम यह फ़र्ज नहीं समझते थे बल्कि अधिकार समझते थे। अब तो हम समझते हैं कि यह हमारा फ़र्ज है, हमारा धर्म है, हमारे समाज का फ़र्ज है, हमारे समाज का धर्म है, और अव्वल फ़र्ज

है और अव्वल धर्म है कि इस चीज़ को मिटा दें, इस चीज़ को हटा दें। मैंने यह माना कि हमने और समाज ने अपने धर्म की अदायगी नहीं की है। यह सबाल किया जाता है कि मैं भी सबर्ग हूँ, मैंने क्या किया? मैंने किया, लेकिन मैंने मिटाने की पूरी कोशिश नहीं की।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखिये बापू जी ने, गांधी जी ने, यह काम शुरू किया। उनके पास १०, १२ या १३ लाख रुपये थे। यही मुझको याद आता है। वह १५, २० साल चला। लेकिन उस १५, २० साल के अन्दर जो काम हुआ, अभा: स्वराज्य के बाद उसका एक हिस्सा भी काम नहीं हुआ है। उनके पास कानून नहीं था। उनके पास रुपया भी ज्यादा नहीं था, सरकार करीब करीब खिलाफ़ हो थी, विरोध हो करती थी, समाज भी कुछ ठंडा था, तो भी जो उन्होंने काम किया, बुनियादी काम किया, हमने नहीं किया। आज नकली काम हो रहा है। मैं मानता हूँ कि नकली काम है। क्या आज जो काम कर रहे हैं उनके पास रुपया नहीं है, कानून नहीं है? मैं यह कहना चाहता हूँ और अपने को समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास कानून है काफ़ी, हमारे पास रुपयों का दरिया बहता है काफ़ी, हमारे पास आर्गेनाइजेशन भी है काफ़ी, लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं यह अपने से पूछता हूँ, समाज से पूछता हूँ कि आज रुपया भी है, कानून भी है, सरकार की नीति भी है तो यह काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस सरकार की नीति जिस कदर अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में है, किसी और चीज़ के सम्बन्ध में नहीं है। प्रोहिबिशन का ही काम ले लीजिये। प्रोहिबिशन के सम्बन्ध में अगर कोई नीति है, कोई पालिसी है, तो वह फ़र्म पालिसी नहीं है, अगर कोई प्रोग्राम है तो कमजोर प्रोग्राम



है। बेसिक एजुकेशन की भी यही हालत है। मेरा इन दोनों में बहुत विश्वास है, लेकिन अस्पृश्यता के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सरकार से कुछ मांग करने में मुझे शर्न आती है। काफ़ी रुपया मिला है, कानून काफ़ी पास हुये हैं, समर्थन काफ़ी हुआ है और हर तरह से समर्थन हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, हमारे भाई ने क्या किया। मैं तो समझता हूँ कि मैंने अपने फर्ज की अदायगी नहीं की। मुझको शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है, मैं कोशिश करता रहता हूँ लेकिन काम नहीं हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाईयों को कुछ गलतफ़हमी है, कुछ जोश है भी। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप अपना मन साफ़ कीजिये कि आप क्या चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण हो, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि अस्पृश्य रहें। That untouchables should remain यह आप चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि यह भी आप नहीं चाहते हैं। अगर यह मांग होती है तो इसका नतीजा यह होता है कि अस्पृश्यता को मिटाओ, जल्दी मिटाओ, लेकिन अस्पृश्यों की जगह होनी चाहिये, मोटी जगह होनी चाहिये, ताकतवर जगह होनी चाहिये। ये दोनों बातें हो नहीं सकतीं। अगर मेरे भाई चाहें कि रुपया ज्यादा मिले तो मिलेगा। ६० करोड़ क्यों २०० करोड़ मिल जायगा। और मिलना चाहिये। मैं लड़ूंगा कि रुपया मिले और अगर कहीं कानून में कोई कमी बेशी हो तो कहूंगा कि ठीक कर दो, दुरस्त कर दो। लेकिन रुपया कौन खर्च करेगा? तुम और हम। कानून का इस्तेमाल कौन करेगा? तुम और हम। आप भी अपने से पूछें कि जो रुपया हमारे हाथ में आया है उसका उपयोग ठीक तरह से किया गया है या नहीं? जो कानून है उस पर अमल पूरी तरह से किया गया है या नहीं? हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है, सबकी गलती है। यह कहना कि तुम्हारी गलती है,

उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम समझें कि हम दोनों की गलती है, हम सबकी गलती है। मैं नअनता से कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ कुछ समझता हूँ और मैं कुछ कुछ इसकी कोशिश करता हूँ कि अपने धर्म का पालन करूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि जिनको हरिजन भाई कहा जाता है वे अब अपने अधिकारों को जानते हैं, काफ़ी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। १०, १५, २० सालों के अन्दर काफ़ी जागृति हुई है। वे अब मांग करते हैं और बहुत जोरों से मांग करते हैं। लेकिन मुझको यह मजबूरन कहना पड़ता है कि अभी वे यह नहीं महसूस करते हैं कि हमारा भी कुछ फर्ज है, हमारा भी कुछ धर्म है। इतिहास मेरा पढ़ा हुआ है और मैं यह मानता हूँ कि किसी भी कौम को, किसी भी कम्युनिटी को, वह अधिकार मिलता है जिसके वह लायक होती है। अगर लायक होती है तो अधिकार मिलता है, अगर लायक नहीं होती है तो अधिकार छिन जायेगा है। अधिकार रुक नहीं सकता, उसके हाथों से निकल जायगा। चाहे औरतें ले लो, चाहे बच्चे ले लो, चाहे स्लेवज ले लो, जब तक उनमें ताकत नहीं आयेगी, शक्ति नहीं आयेगी, जब तक वे कुर्बानी नहीं करेंगे, तब तक उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं आने वाला है।

मैं यह चाहता हूँ कि कानून हो। मैं भी कोशिश करूंगा कि कानून की ताकत लेकर अस्पृश्यता का हम निवारण करें। लेकिन आप भाइयों से भी मैं यह कहूंगा कि आप भी कुछ करें। आप में से बहुत से वकील हैं। क्यों नहीं आप हरिजनों को फ्री लीगल ऐडवाइस देते हैं? मैं इससे भी बढ़कर कहता हूँ कि अस्पृश्यता की जो एक दीवार है, वह एक बेबुनियादी दीवार है। अस्पृश्यता को बुनियाद बहुत कच्ची है। गांधी जी ने उस बनि-

[श्री ना० २० मल्कानी]

याद को हिला दिया। जिसे महात्मा बुद्ध ने नहीं हिलाया, उसे उन्होंने हिला दिया। यह मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। मुझे इसके लिये कोशिश करनी चाहिये, लेकिन आप भी कुछ करें। असल में आपको ज्यादा जोर लगाना चाहिये क्योंकि मुसीबत ज्यादा करके आपको है। अगर आप यह कहें कि मल्कानी करे, तो मल्कानी करता है और करता रहेगा, लेकिन हमको आपकी मदद चाहिये, बल्कि ज्यादा चाहिये क्योंकि you are greater sufferers. यह मुसीबत आप पर ज्यादा है, आपको सफरिंग ज्यादा है। तो आप आज कल ज्यादातर सैमिटिव भी हो गये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रेजिस्टेंस करें। दिल्ली को ही ले लोजिये, यहां काफ़ी कैफ़े और रेस्टां हैं। आप हमें ले चलें, कल हो चलेंगे, मिल कर जल्था बांध कर हम ५० आदमी उन पर चढ़ाई करेंगे, कैफ़े और रेस्टां में जायेंगे। देवकीनन्दन भाई को आगे बढ़ायेंगे और मैं मानता हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूंगा और हम सब रेजिस्टेंस करेंगे। तो मैं यह मानता हूँ कि आप रेजिस्टेंस करें, जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा और रिजर्वेशन होगा तो काम नहीं चलेगा। तो आपका शब्द 'रेजिस्टेंस' होना चाहिये, जैसे कि 'सिविल रेजिस्टेंस' शब्द है। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहां 'रिजर्वेशन'—शब्द कहा जाता है। उससे काम आगे नहीं बढ़ेगा। अभी एक साहब ने कहा कि उससे तो कुछ काम बिगड़ेगा और वह बिगड़ गये लेकिन मैं मानता हूँ कि उससे हरिजन भाइयों को ज्यादा नुकसान होता है।

श्री पा० ना० राजनोज : आप तो हरिजन सेवक संघ के मेम्बर हैं ?

श्री ना० २० मल्कानी : माफ़ कीजियेगा, हो सकता है कि मेरी गलती हो लेकिन मुझको यह डर है कि समाज को

तो इस से धक्का पहुंचेगा ही, लेकिन कहीं हरिजन भाइयों को भी इस से धक्का न पहुंचे और व भी कहीं फंस न जायें। जब एलक्शन की कोशिश होती है तो हम खुद ही उस में फंस जाते हैं। आज सुबह लाबी में एक भाई का दिमाग बहुत गर्म हो गया। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी गर्म हो गया होता। यों ही मैं गर्म हूँ और बुढ़ापे की वजह से गर्म हो जाता हूँ। तो यह 'गर्म दिमाग' से काम होने वाला नहीं है। 'गर्म दिल' से होने वाला है। 'गर्म दिल' के माने यह है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना।

श्री रानेश्वर अग्निभंज : वह तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, बर्फ़ हो गया है।

श्री ना० २० मल्कानी : लाबी में तो हम एक दूसरे को गोद में ले लेते हैं लेकिन जब यहां रिजर्वेशन का सवाल आता है तो बकवास चलती है और चैलेंज चलता है। इसलिये अच्छा है कि यह सवाल न आये, फिर भी, हां, मैं कहता हूँ कि जब यह आपकी मांग है और इस पर वोट लिये जायेंगे तो इसके लिये मैं अपना हाथ जरूर उठाऊंगा और अगर हो सका तो दो हाथ भी उठाऊंगा लेकिन फिर भी लाबी में जा कर धीरे कहूंगा कि यह बात ठीक नहीं है, इस पर इतना जोर न दो और रेजिस्टेंस पर जोर दो। इस पर जोर न दे कर हम सब मिल कर 'रेजिस्टेंस' करें। गांधी जी हर वक्त तो हैं नहीं और बिनोबा जी हर वक्त आते नहीं है, आ नहीं सकते हैं, इसलिये हमारे ही संगठन से काम होने वाला है। यह 'हरिजन' और 'नान-हरिजन' का खयाल बुरा है और इस खयाल की वजह से हरिजनों पर ही ज्यादा मुसीबत आयेगी। They are sufferers and we are inflictors. इसलिये उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। आप रिजर्वेशन की मांग करें, कानून की मांग करें,

स्पे की मांग करें तो वह भी पूरी करनी होगा, आप रिजर्वेशन कहेंगे तो रिजर्वेशन होगा, जो कहेंगे वह होगा लेकिन मेरा खयाल है कि इस से काम बनने वाला नहीं है। हम सब को चाहिये कि मिल कर रेजिस्ट करें और असुश्यता को ही नहीं बल्कि असुश्यताओं को भी निकाल दें।

SHRI R. P. TAMTA (Uttar Pradesh): Mr. Deoutv Chairman, this is a very important matter which concerns not only about eight crores of scheduled castes and scheduled tribes but the whole country because, on a decision of the question which is before the House would largely depend the future progress of our country. Let us see, Sir, the Resolution as it stands. It seeks to amend article 334 of the Constitution which provides that reservation with respect to the scheduled castes and the scheduled tribes would terminate after a period of ten years from the commencement of the Constitution. By this Resolution, my hon. friend, Mr. Rajabhoj, wants that the period of reservation should be extended to twenty years instead of ten years. Before dealing with the question of reservation as a whole, I would request the House to take into consideration the factors and the circumstances which led the framers of the Constitution to embody in the Constitution a provision with respect to the reservation for the scheduled castes and the scheduled tribes and also the reason why they have fixed a period of ten years only. When we go and look at it, we find that the Advisory Committee on minorities, in its meeting of the 8th August, 1947, had decided that the reservation for the minorities as a whole, including the scheduled castes and the scheduled tribes, should be for a period of ten years and further there was a provision that thereafter the whole question would be reconsidered. Later on, in its meeting of May, 1949, it was decided that the reservation with respect to the scheduled castes and the scheduled tribes would remain and that the

reservation with respect to the other communities, that is the Muslims, Christians and Sikhs should go, but the Committee did not say anything as to what would happen with respect to this reservation after the expiry of ten years, as was the decision of the 1947 meeting.

As I had submitted earlier, to understand this question, we have to look into the question of reservation. Personally I feel that there are two conflicting opinions prevalent among the scheduled castes with respect to this question. There is a section of the community which feels that this spoon-feeding, that is the reservation, which in a way has demoralised the community and has retarded its progress and has made it dependent on the sweet-will and mercy of others, should go because, only then would the community be able to stand on its own feet and will be able to fight for its rights and progress rapidly. Sir, this is one aspect, and there is the other aspect of the question. There are certain persons who hear that in case there is no reservation the members of the scheduled castes and the scheduled tribes will not be able to fight and contest elections and come out successful in the contest against people of other castes. This fear is also borne out by the facts as we see. In the present composition of the various upper houses, the Legislative Councils in the States, and the Rajya Sabha here, we find in these bodies that the representation of the scheduled castes and the scheduled tribes is hardly 1 per cent, or even less than that, and in the Rajya Sabha, it is hardly 3 per cent, while in the Lok Sabha and the State Assemblies, due to the reservation of seats for the scheduled castes their representation is about 15·5 or 15·4 per cent. When we look at the facts we fear that, if there is no reservation, the members of the scheduled castes may not be returned to the Legislatures in proportion to their numerical strength. Why it is so and how it can be remedied are questions which we have to take into consideration. As a matter of fact, democracy and reservation do

[Shri R. P. Tamta.] not go side by side. Democracy presupposes equality, and when there is adult franchise, the idea of reservation looks rather odd. But, in our country, the actual condition of the people inhabiting here, the social disabilities and the various atrocities which the Harijans had to suffer on account of various factors in the past and which had led them to lag far behind in the march of rrien, had to be taken into account, and the framers of the Constitution thought, and I think rightly thought, that if there was no reservation for these communities in the Legislatures, members of these communities would not be returned to these august bodies and will not be able to place before the Assemblies and the Lok Sabha the grievances and the disabilities and the problems connected with the scheduled castes and the scheduled tribes. This departure was, therefore, made; an exception was made in the case of these communities, and a provision was embodied in the Constitution giving them reservation. If you were to compare the conditions prevalent at the time the Constitution was framed and the conditions prevailing at present, you will find that there has been some difference in the economic, social and educational condition of these classes. Even then they are very backward and they will not be able to compete on equal terms with the persons belonging to other castes. Thus the

object with which this reser-3 P.M.  
vation was granted by the

Constitution makers is still there. So, I think it is necessary that some means should be devised to see that the members of these communities get a fair representation in the various Legislatures.

As the time is short, I will not go through the various reports of the Commissioner for Scheduled Castes, which go to show that although un-touchability stands abolished under article 17 of the Constitution, it is still observed in some form or other, more particularly in rural areas. The persistence of caste distinction and caste prejudices constitutes a challenge to

our nation. It is, however, gratifying to note that the discrimination based; on caste prejudices, though deep-rooted, is gradually weakening its hold on the progressive elements in our society. Again, as far as forced labour is concerned, the Report says, "it is true that this practice is not found generally except in rare cases and in some of the interior areas, but it is still prevalent in one form or other." So, the various disabilities, the consideration of which had led the framers to make provision with respect t& reservation of the scheduled castes,, are still there. Therefore, something; I think has to be done.

As I have submitted earlier, there has been some change and change for the better. It is not that if the members of the scheduled castes contest elections they will not be able to come out successful. It is not so. There have been instances when the scheduled caste people fought elections and they were successful in general seats. I know the case of my own district, A'mora, which is regarded as an orthodox district. There I know personally of the case of a relation of mine Sri Hari Prasad Ji Tamta who fought a direct election for the chairmanship of the municipal board and he got the highest number of votes of the caste Hindus. He was chairman: of the municipal board. He was elected by the caste Hindus. He remained there for seven or eight years. So, it is the capability of a man, it is his work, his service, that is taken into consideration by the people at the time when they elect him to the various posts. As I have said, mine has been an orthodox district as it is called. There too if a scheduled caste man has some service to his credit-then he is able to compete with others and there have been instances when the scheduled caste people had been-returned from the general constituencies, in the Vidhan Sabhas and the Lok Sabha also.

As far as the question of reservation. is concerned, my submission would be that even if the reservation is termi-

nated, as is provided in the Constitution, there can be another way out. There can be a *via media*. Let the reservation be terminated, but there should be some amendment of the Constitution with respect to articles 331 and 333. These articles say that in case the representation of the Anglo-Indians is not in adequate number in the Legislatures, the President and the Governor will have the power to nominate them in the Legislatures. Similarly, if you want to give up the reservation, and decide that the period of reservation should not extend, then the Constitution should be amended suitably. We might say that the reservation would go and the members of the scheduled castes and scheduled tribes should contest in general election. And if they are not returned in sufficiently, large numbe2-s in the various Legislatures, there should be a provision in the Constitution saying that the President or the Governor, as the case may be, might nominate members from that community in the Lok Sabha or the Vidhan Sabhas. This can be the one way to ensure fair representation. This will be my suggestion because I feel that as long as the reservation would remain, the scheduled castes and scheduled tribes might not be able to progress rapidly and stand on their own feet.

As far as the reservation in the Services is concerned and the special facilities for them in the educational field is concerned, I think it is imperative that reservation in the Services should stand and the special facilities for them for their educational advancement should be there. I would suggest that a period of ten years might be provided. During these ten years, the power to nominate members of the scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha be given to the President. And during that period there should be (*Time bell rings.*) free education for the scheduled castes and scheduled tribes in all stages and there should be reservation in the services and the Government should see that these provisions for reservation in the services

1-20 RSD—3

&amp;

and for their educational development and economic development are fully implemented, so that after, say, ten years, when that provision goes away the scheduled castes and scheduled tribes might be able to come into level with the rest of the people of the country. Our democracy can only be successful when all people, of different castes and communities are equal in all respects and get equal opportune- • ties for development and all that.

Finally, I would say that for th« successful progress of our democracy, the greatest obstacle that comes in the way is the caste system and unless the caste system goes away the dis-: tinction between high and low, between the upper caste and lower caste would remain. I know there ar« social reformers like Santramji and others who have established *Jatpat Todak MandaV* and sponsored inter-caste marriage and all that. Government should also see to that aspect of the question and should do everything possible, so that after some years there will be no occasion for th« scheduled castes and scheduled tribes to come forward and ask for further extension.

श्री राम सहाय ( मध्य प्रदेश ) : उप-सभापति महोदय, यह प्रस्ताव जो हमारे सामने है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। मेरा यह खयाल जरूर है कि यह प्रस्ताव बजाय इसके कि हमारे एक हरिजन भाई, हमारे इस सदन के सदस्य, पेश करते किसी सवर्ण की तरफ से यदि आता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि उन्होंने अभी कुछ जल्दी की, क्योंकि हममें से बहुत से लोग इस बारे में विचार करते थे कि हरिजनों और आदिवासियों के लिये रिजर्वेशन की अवधि और बढ़ाई जानी चाहिये।

अभी वृहत् में कुछ इस प्रकार की बात सामने आई है कि हमें उन हालात पर गौर करना चाहिये जिन हालात में हमने कांस्टी-ट्यूशन में दस साल का समय रखा था। यह बिल्कुल सही बात है। मेरा तो यह

[श्री राम सहाय]

निश्चित मत है कि हम इस मामले में जहाँ के जहाँ ही हैं। यदि कहीं थोड़ी बहुत उन्नति हुई है तो यह इस बात के लिये काफी नहीं है कि हम यह समझें कि अब इस रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं रही है। इसका टेस्ट मैं यह समझता हूँ कि हम इस बात को देखें कि हमने दूसरे पहलुओं पर हरिजनों के साथ क्या किया, तब हम यह समझ सकते हैं कि दरअसल हमने उनको सुयोग्य बनाने में कोई कोशिश की या नहीं।

जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जो पहले क्लास के मुलाजिम हैं, उनकी तादाद हजारों में है और मैं समझता हूँ जहाँ उनमें से पाँच पाँच सौ, पौने पाँच सौ या चार सौ तक आदमी एक एक डिपार्टमेंट में होंगे, वहाँ भी हरिजनों की संख्या एक या दो या तीन से अधिक कहीं भी नहीं है, और अगर केन्द्र के सभी फ्रंट क्लास मुलाजमान से उनकी कुल संख्या का मुकाबला करके हम देखें तो गवर्नेट फ्रंट क्लास पोस्ट्स में केवल बीस या इक्कीस आदमी मालूम देते हैं, और वह भी शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूलड ट्राइब्स दोनों को मिला कर। जहाँ हजारों की तादाद में हमारे मुलाजिम हैं वहाँ इन लोगों की संख्या इतनी थोड़ी है।

जब देश में इस तरह की परिस्थिति है तो हमें यह बात खयाल करनी चाहिये और सोचनी चाहिये कि इस समय जो परिस्थिति है उसमें संतोष मानना बिल्कुल बेमानी सी बात है। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त सर्विसेज की बात छोड़ दीजिये। आप राज्य सभा को देखिये, विधान परिषदों को देखिये, आप किसी भी लाइन पर चले आइये आप इस बात को पायेंगे कि इनका उन्नयन में जितना परसेंटेज

मिलना चाहिये था उतना नहीं मिल रहा है। देश की जनसंख्या ३६ करोड़ के करीब है। उसमें से ८ करोड़ के करीब इनकी संख्या है, इस हिसाब से परसेंटेज हमारे इन भाइयों को मिलना चाहिये था मगर मिलता नहीं है। स्कूलों में इन लोगों को जो सुविधायें मिली हुई हैं उनका भी वे लोग अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके बच्चों को चरवाही और दूसरा घरेलू काम करना पड़ता है जिसकी वजह से वे पढ़ने को स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। हम शायद यह खयाल करते हैं कि इन लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है जो मेरे खयाल से मनासिब नहीं है। मैं आप से कहता हूँ कि आप फ्रंट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सर्विसेज वालों की बात को छोड़ दीजिये, चौथे क्लास सर्विसेज में इन लोगों को जो परसेंटेज मिला हुआ है क्या वे उसका पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी देखता हूँ कि इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो अफसरान साहब हैं वे इस तरह के नौकरों को दफ्तर में नौकर रखते हैं जो ब्राह्मण हों ताकि उनका भोजन बना सकें या घर का कोई काम कर सकें। वे हरिजन भाइयों में से दफ्तर में किसी को चपरासी या दूसरी जगहों में इसी कारण से नहीं रखते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि चौथी श्रेणी में जहाँ इन लोगों को आसानी से जगह मिल सकती थी वहाँ भी उनको नहीं मिल पाती है। हमारे देश में इस तरह की परिस्थिति हो रही है और हम इस अभिशाप के लिये रोते चले आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यह बात हम नहीं देख रहे हैं। हमें जिस तरह का सहयोग अपने हरिजन भाइयों को देना चाहिये था उस तरह का सहयोग हम नहीं दे पा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि लोग ऐसा समझते हैं कि हम हरिजनों के लिए

कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ करते हैं अपने लिये करते हैं। अगर हम इस चीज को पोलिटिकली देखें, धार्मिक खयाल से देखें चाहे किसी पहलू से देखें यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनको जितनी जल्दी हो ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाये उतना ही वह हमारे देश के लिए अच्छा होगा।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने हरिजन-कार्य को आरंभ ही से राजनीतिक दृष्टि से नहीं उठाया एक धार्मिक दृष्टि से उठाया और स्वामी दयानन्द जी ने जिस तरह से इस कार्य के लिए आदेश दिया उसी तरह से मैं ५० वर्ष से ऊपर हो गये हैं, यह कार्य करता आ रहा हूँ। मैंने अपने देश के लोगों की मेन्टैलिटी को यथोचित बदलते नहीं देखा और फिर भी हम शिकायत करते हैं कि हरिजनों में आपस में कई वर्ग हैं, जातियाँ हैं और पार्टियाँ हैं। लेकिन हम अपने आप खुद को नहीं देखते हैं कि हम कितनी पार्टियों में बंटे हुए हैं। मेरा मत है कि हरिजन फिर भी सबर्गों के बजाय संगठित हैं और आदिवासियों में भी यही हालत है। हम लोगों का उन लोगों के प्रति इस तरह की बात सोचना मुनासिब नहीं है।

हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं कि इस रिजर्वेशन से उनकी सपरेटिस्ट टेन्डेंसी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है? मैं समझता हूँ इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है जो अपने आपको विद्वान कहते हैं। शास्त्री कहते हैं, साधन सम्पन्न कहते हैं और पढ़ा लिखा कहते हैं। जब हम अपने में से यह दोष नहीं हटा पा रहे हैं तो हरिजनों से इस तरह की अपेक्षा करना हमारी कुछ योग्यता की निशानी नहीं है।

जिस काम को हम स्वयं नहीं कर पा रहे इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाये हैं तब हरिजनों से इस तरह की आशा करना कि थोड़े समय के अन्दर वे अपने को बदल लेंगे, मुनासिब मालूम नहीं पड़ता है।

यह कहा जाता है कि हमारे हरिजन भाइयों में काबलियत नहीं है। इस संबंध में मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रखना चाहूँगा। मैं जिस स्थान का रहने वाला हूँ उसे भिलसा-विदिश कहते हैं। वहाँ का एक हरिजन लड़का मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त है। इसी तरह से एक नाई का लड़का हमारे यहाँ से भोपाल मेडिकल कालेज में डाक्टरी पढ़ने के लिए गया हुआ है। उसे अपनी काबलियत के लिहाज से गवर्नमेंट स्कालरशिप भी मिलता है। उस कालेज में बकीलों के, डाक्टरों के और दूसरी जाति के लड़के पढ़ते हैं मगर वह उन सबमें पहला आता है। तो आप गौर कीजिये कि कोई किसी खास जाति के लिहाज से ऊंचा नहीं हो सकता है बल्कि जिसको जितना ऊंचा उठने का मौका मिलता है उतना वह आगे बढ़ता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम कहते तो यह हैं कि हरिजनों की हर प्रकृति की सुविधा दी जानी चाहिये लेकिन होता यह है कि उनको पर्याप्त मात्रा में उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता है। जिस तरह के विचार सदियों से हमारे दिमागों में थे वही आजकल भी चले आ रहे हैं। हमारे जिले भिलसा में सिरोंज एक जगह है जहाँ पर एक कुण्ड है। आज से दो वर्ष पहले वहाँ पर किसी हरिजन को नहाने या पीने के लिये पानी नहीं भरने देते थे। यहाँ तक नाबत आई कि जगड़ा हो गया और दो हरिजन मारे गये। मगर आज वह परिस्थिति नहीं है। अब वहाँ पर हरिजनों को नहाने और

[श्री राम सहाय]

पीने के लिए पानी भरने दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमारे देश में आज भी इस तरह की परिस्थिति मौजूद है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार से इस तरह की बुराईयां हमारे देश से दूर हो सकती हैं। केवल हरिजनों को दोष देना मुनासिब नहीं है।

मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्ताव में जो दस वर्ष का समय बढ़ाने को कहा गया है वह अधिक नहीं है। मैं अपने साथियों से यह निवेदन करूँगा कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि इस अवधि यानी चार साल जो बाकी है और आगे दस साल जो बड़े हम इन चौदह सालों में इस समस्या को हल कर सकें तो भी हमें अपने आपको भाग्यशाली समझना चाहिये। दस साल तो आप इस प्रस्ताव के कारण बढ़ाना चाहते हैं और चार साल अभी बाकी पड़े हैं। मुझे इसमें संदेह मालूम होता है कि हम इस अवधि में इस कार्य को पूरा कर सकेंगे या नहीं। मैं होम डिपार्टमेंट से निवेदन करूँगा कि उसे इस सिचुएशन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या वजह है हमारे आफिसर हरिजनों, मेहतरों और चमारों को चपरासी, फराश आदि दूसरी छोटी नौकरियों में क्यों नहीं रखते हैं। इन जगहों के लिये किसी तरह की काबलियत की जरूरत नहीं होती है तो फिर क्या वजह है इन लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जाता है और उनका कोटा उनका परसेंटेज जो उस जगह के लिए सुकरर है पूरा नहीं किया जाता। मेरा निवेदन यह है कि जो परसेंटेज उनके लिए सुकरर है वह उनको पूरा मिलना चाहिये। अगर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास में

इन लोगों को परसेंटेज के मुताबिक नहीं रखा जा सकता है तो कम से कम चौथी श्रेणी में तो उनका परसेंटेज पूरा होना चाहिये। जो नीची जगहें हैं उनमें कम से कम उनका कोटा ५० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिये। अगर हमने यह बात कर दी तो मुझे आशा है हम उन लोगों की बहुत सहायता कर सकेंगे। वैसे यह भी कहा जाता है कि उन लोगों के करने के लिये दूसरे धंधे भी हैं मगर वे सबके लिए एकसा हैं जब तक सरकार इस ओर अग्रसर होती दिखाई नहीं देती है जनता से भी ऐसे कार्यों में समर्थन नहीं मिलता है और न ही वह साथ देती है। इस लिए मेरा यह निवेदन है कि होम मिनिस्ट्री इस बारे में हर डिपार्टमेंट के लिए सलाह तौर पर इंस्ट्रक्शन भेज दें कि जो नीची जगहें हैं उनमें इन गरीबों को ही लिया जाय। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अब्दुर रज्जाक खान (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, जो प्रस्ताव आनरेबल राजभोज साहब हाउस के सामने लाये हैं वह पोलिटिकली बहुत ही अहम है। हम इस बात को सोच ही रहे थे लेकिन उन्होंने इसको सदन के सामने लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

मैंने यह अर्ज किया कि यह बात मियामी तौर पर बात अहम है। प्रस्ताव के जो माने हैं, जो मकसद है, जो उसमें कहा गया है, वह भी यही है कि मियामी रिप्रिजेंटेशन यानी पोलिटिकल रिप्रिजेंटेशन जो चल रहा है, जो रिजर्वेशन से बक्त है, वह कायम रहे, उसकी मियाद आगे बढ़ा दी जाय, दस साल से बीस साल कर दिये जाय। लेकिन अगर यह टाइम कुछ कम भी हो, तीन इलेक्शंस के बजाय दो ही



इलेक्शन के लिए रख दिया जाय, तब भी मेरे खयाल में प्रस्तावक को यह नामंजूर नहीं होगा।

बहरहाल, मन्त्रालय यह है कि कांस्टिट्यूशन में जो इस वक्त दस साल का रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय। कांस्टिट्यूशन का मकसद जहां तक मैं समझता हूं वह यही है कि उन्होंने पहले यह मान लिया है कि रिजर्वेशन रखना चाहिये, उसके बाद उन्होंने दस साल का कम से कम पीरियड रखा। उनका मकसद यह था कि रिजर्वेशन हमेशा के लिए न रहे, इसको एक न एक दिन हटा देना है। इसलिए कम से कम वक्त रक्खा गया। उसके बाद क्या सूरत होगी यह आइन्दा के लिए लोगों पर छोड़ दिया गया है कि लोग गौर करेंगे, अगर जरूरत समझेंगे तो इसको बढ़ायेंगे, अगर जरूरत नहीं समझेंगे तो खत्म कर देंगे। चुनावों इसमें कांस्टिट्यूशनल बार कोई नहीं है। अब गौर करना यह है कि दस साल खत्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम आगे दस साल के लिए बढ़ायें या न बढ़ायें। तो इसका हमें रिकॉर्ड करना है, यह देखना है कि इसकी वर्किक कौसी हुई। जो मकसद है कौमी इतिहाद का वह इसमें आगे बढ़ा या नहीं, यह जो मेजूर (measure) लगाया गया, इसमें यह मामला कुछ आगे बढ़ा या नहीं, इसमें कुछ फायदा हुआ या नहीं, हरिजनों को आप अपनी तरफ कुछ खींच सके या नहीं, उनमें मेल जोल का कुछ रिश्ता बना या नहीं। मैं देखता हूं कि आज हजारों लाखों की तादाद में हरिजनों में से कैडर बन गये हैं जो एक पुल का काम करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पूरा काम हो गया है। मैं यह भी नहीं कहता कि कुछ भी नहीं आ है और आज वही हालत है जो दस साल पहले थी। मैं यह कहता हूं कि आज सूरत पहले से

बहुत बेहतर है। आज इलेक्शन के नतीजे देखिये। आज सब पार्टियों का हरिजनों पर दारीमदार है। आज गैड्यूस कास्ट का लोग दूसरे लोगों के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें कौमी इतिहाद में बहुत मदद मिल रही है। इसलिए इस रिजर्वेशन को कुछ दिनों के लिए और बढ़ाना जरूरी है। आज लाखों की तादाद में जो कंडर कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, १० एस० पी० वगैरह में हैं वह हरिजनों में आये हुये हैं और पोलिटिकल मैदान में काम कर रहे हैं। आप उनसे पूछिये कि इस सिलसिले में उनकी क्या राय है। जब वह आपके साथी हैं, आपकी पार्टी के अन्दर हैं, आपकी पार्टी के रुकन हैं, तो उनसे पूछिये कि उनकी क्या राय है। अगर वे यह राय दें कि यह सूरत दस या १५ साल और रहनी चाहिये, तो आप ऐसा कर दीजिये। जब हरिजनों में आपको बहुत काम लेना है तो उनकी राय के मुताबिक काम कीजिये। आज हरिजनों को हरिजनों में उठाया जा रहा है और यह जो सूरत खनी हुई है इसको इतनी जल्दी खत्म करने की कोई वजह नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी और इस सिलसिले को काट देने में तरक्की का रास्ता रुक जायगा।

ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता और न ज्यादा कहने की जरूरत है क्योंकि बहुत से आनरेबिल मेम्बरों ने इस पर काफी रोशनी डाली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन को अभी कुछ दिन और कायम रखा जाय। अगर फैसला दूसरे किस्म का आ तो उसमें बहुत नुबसान होगा। मैंने यह देखा है कि जो कौमी मैदान में काम किये हुये लोग नहीं हैं, जो कम्युनल हैं, ऐसे लोग हरिजनों के अन्दर इलेक्शन में कामियाब नहीं हो सकते। जिन हरिजन भाइयों के जरिये यह काम हो रहा है, वे आज लाखों की

[श्री अश्वदुर रज्जाक खान]

तादाद में पोलिटिकल मैदान में हैं, पोलिटिकल पार्टियों में हैं। इसलिए अगर उनको राय यही है कि मौजूदा रिजर्वेशन की मूरत भायम रहे, तो आपको उनको राय के मुताबिक काम करना चाहिये। जब उनकी यह राय हो कि अब जरूरत नहीं है, अब फिजा ऐसी हो गई है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तभी आपको इसे उठाना चाहिये।

बहुत मे हमारे आनरेबिल दोस्तों ने यह कहा है कि रिजर्वेशन रखने में कौमी इतिहाद टूटता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह खयाल सही नहीं है। इन दस सालों की तवारीख गवाही देती है, हमें यह बताती है कि इसमें कौमी इतिहाद बढ़ा है, घटा नहीं है। हमें एक फामूला, एक डागमा नहीं क्रिएट करना चाहिये। यहां ज्वाइंट इलेक्ट्रेट की बुनियाद पर यह रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें वह नतीजा नहीं निकलता जो सेप्रेट इलेक्ट्रेट में निकलता है। यह समझने की बात है। मैं समझता हूं कि आज काफी लोग यह कहेंगे कि हमें बहुत नतीजा निकला है और इसमें हरिजनों को अपनी तरफ खींचने की एक मूरत बनी है। मैं समझता हूं कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हरिजनों को सियासी तौर पर आगे बढ़ाया जाय। वह नहीं होना चाहिये कि हम उनको कुछ सेवा कर दें लेकिन पोलिटिकली उनको गिरा कर रखें। उनको आगे बढ़ाने का कोई तरीका है तो यही है कि पोलिटिकल पार्टिज में उनको ज्यादा से ज्यादा लिया जाय। इसलिए इस मूरत को इतनी जल्दी खत्म करने की कोई वजह नहीं है।

मैं और न कह कर इस प्रस्ताव का बहुत जोरों के साथ समर्थन करता हूं।

Castes and the Scheduled Tribe would bring in a resolution which would, in a way, be affecting all the backward people. He has brought this Resolution for the sake of a few who are Members of Parliament and who are Members of the Assemblies. He has not touched the main question as to how far these ten years have improved the condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I thought probably he would bring in some sort of a comprehensive resolution. Sir, what would be his reply; to the electorate when they ask him whether he did anything to get reservation for them? The only reply he can give is "Yes, I had brought in a resolution for myself and for a few others."

Then, Sir, another question then arises is how far this reservation is essential. Has it brought unity? Has it brought solidarity? Has it created friendship, or has it created a division? This matter is of a very serious nature. One has to consider it very carefully and see if the air with which we had started has been fulfilled by these reservations. I am neither opposed nor am I in favour of this Resolution, but I do wish that the whole matter has to be gone through, carefully studied and then a decision arrived at. We find in the Constitution in article 338 it is said

"The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Area and the welfare of the Scheduled Tribes in the States ..."

So that a Commission has to be appointed. Now, this matter may also be referred to that Commission because the present Assemblies and the Parliament will continue till 1962. There is no feverish hurry. This matter is not closed as yet. We have to carefully consider these things. To my mind it appears that the time has come when a clear distinction has to be made between the backward people

SHRI MAHESH SARAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thought that our great leader of the Scheduled

\*nd others. The backward people are lot the Scheduled Castes and Sche-Juled Tribes but the backward people ire the poor people of India and we should try and see that their development also is taken in hand side by side with the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have been strongly feeling about it as I have moved about in tillages and have seen the conditions )f the poor people. They are now a ■lass by themselves, whether they be Hindus, Muslims or Scheduled Castes or Scheduled Tribes. **Even** Scheduled C<sup>D</sup>ste and Scheduled Tribe people, if th. > are officials, have res-ject shown to them but poor Brahmins, poor Khatris or poor Sche-uled Castes have no attention paid o them. Therefore, my submission is hat we have also to see whether we ihould not in future, make plans by which the Scheduled Castes and Sche-luled Tribes and the other poor peo->le are looked after properly.

There is another point which is worthy of serious consideration, and t is whether within the Scheduled Pastes themselves we are not having mall groups of different castes, and itention has to be paid to this, so hat this feeling of difference among hemselves may disappear. We should ry to have a united India consisting >f the Scheduled Castes and all the >ther castes working together. There-ore, my submission is that, instead of leiding this question now, a Commis-ion should be appointed to go into the vhole question and see whether it is idvisable to have this period extended tfter the expiration of ten years.

**श्री क० बि० लाल (बिहार) :** उप-भभाषति महोदय, मुझे भी कुछ दैपी ही मंकट की अवस्था मालूम होती है जैसी कि प्रोफेसर मल्कानी साहब ने अपना भाषण देने में अपने लिये कही थी। मेरे जो विचार हैं उनको मैं इस सदन के सामने पहले भी रख चुका हूँ कि इन बातों में मैं सहमत नहीं रहता हूँ कि छुप्राछून या अछूतपन को उठाने के बदले अछूतों का संगठन किया जाय। मेरे

मित्र राजभोज जी जानते हैं कि मैंने अपने पहले के भाषण में कहा था कि मेरा ख्याल है कि छुप्राछून और अछूतों को एक दम खत्म कर देना चाहिये। यह एक बड़ी दृखद बात मालूम होती है। कहीं इसका मिमंडरिप्रिटेगन कोई करे तो ऐसा मालूम होगा कि यह अछूतों को खत्म करना चाहते हैं। बात तो कुछ ऐसी ही है और कोई यह नहीं चाहता है कि अछूत देश में बने रहें लेकिन इस संशा से अछूत बनें कि हम अपना मतलब साथे उनके अस्तित्व से, उनके रहने से हमारा मतलब साथे तो यह बड़े अफ़ांस की बात होगी। हम सब एक ही राय में मस्त हो जायें, इस बात में फ़नेटिक हो जायें कि अछूतपन को उठाना है और कोई अछूत देश में नहीं रखना है तो इस बारे में मेरा ख्याल भी वैसा ही फ़नेटिक है जैसा कि स्वर्गीय अम्बेदकर साहब का था। वह अछूतपन से ऊब कर के और समाज की अवस्था को देख कर के यह कहने लगे कि किसी भी हालत में अछूतपन नहीं रहना चाहिये और वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसीलिये वह इस समाज को छोड़ कर दूसरे समाज की शरण लेना भी पसन्द करते थे। मैं भी उनके साथ हूँ न मेरे कई और भी मित्र थे जो कि अछूत नहीं थे—ऐसा कहा करते थे कि साहब अछूत अगर मैं होता तो मैं एक रोज भी इस समाज के अन्दर नहीं रह सकता था, मैं तो किञ्चियन हो जाता। तो मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। हम तो उनको सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इतनी मुसीबत में रह कर भी वे सनातनी समाज में हैं। मैंने सनातनी शब्द का व्यवहार जानबूझ कर किया है। अम्बेदकर साहब यह गलती करते थे जबकि वह कहते थे कि हम हिन्दू ही नहीं रहेंगे, हम मुसलमान हो जायेंगे। मुसलमान होने से भी तो आदमी हिन्दू बना रह सकता है किञ्चियन होने से भी हिन्दू रह सकता है इसलिये हम उनसे कहते थे कि आप यह कहिये कि हम सनातनी समाज में नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि चाहे जिस तरिके से हो यह अछूतपन यहां से उठे और कोई अछूत हमारे

[श्री. कै० बि० लाल]

मुल्क में नहीं रहे लेकिन समस्या इतनी कठिन है कि गवर्नमेंट के लिये भी कोई इसका सुलझाव नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने अपने संविधान में भी इस तरह की बात लिखी है कि जिसकी बुनियाद पर आज इस तरह का प्रस्ताव भी आया है लेकिन अपनी सरकार से मेरा मुझाव यह है कि इन बातों में वातावरण को एटमस्फीयर को खराब नहीं करना चाहिये। इसको इस तरह से बेहम और दलील में लाकर के देश के अन्दर इस बात का प्रचार करना है कि हम जुदागाना अस्तित्व के मानने वाले हैं हम में जुदागाना अस्तित्व की बहुत सी भिमाल है, बहुत सी बुनियाद है और इसके ऊपर हम इस तरह से लड़ भिड़ सकते हैं। आज इस सदन के अन्दर भी जो वातावरण पैदा हुआ और जिस तरह के गर्मागर्म आख्यान हुए वह दिल को बहुत दुःख पहुँचाने वाली बात थी। कुछ भाइयों ने इस तरह की तू तू और मैं मैं की बात की। अब इसके लिये दोष किसे दिया जाय ? बुराई तो अपने अन्दर है और सरकार भी ऐसी नीति या अवलम्बन किये हुए है कि यह बुराई भी जूट रहे और यह विभिन्नता फैलती रहे।

अब यहाँ एक बहुत बड़े उसूल की बात आ जाती है कि यह डेमोक्रेसी में तय हो सकता है या नहीं हो सकता है। यह बड़ी दुखद बात है। हम लोग सब डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं और बहुत सी बातों में कम्युनिज्म से या और दल बातों में हमारा मतभेद है क्योंकि वे जबरदस्ती काम कराना चाहते हैं। लेकिन इस छुआछूत से, जाति पात से और समाज की दशा को देख कर उससे, मेरा जी तो इतना ऊबता है कि मेरा ख्याल यह होता है कि कहीं ऐसा उसूल हो जाय जो कि डेमोक्रेसी के नाम पर इस वातावरण को खराब नहीं होने दे और जबरदस्ती लोगों से इस पाप को छुड़ाये। यह ऐसा पाप है, ऐसा कोढ़ है समाज का कि जो डेमोक्रेसी के नाम पर भी, एक

क्षण नहीं रहने दिया जाना चाहिये और इस तरह के वातावरण को भ्रष्ट नहीं करने देना चाहिये। लेकिन क क्या ? हम तो डेमोक्रेसी से सम्बन्धित हो गए हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर इसमें भी दलीलें करते हैं क्योंकि हर एक आदमी को बेहम करने का मौका है, हर एक आदमी को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है स्वतन्त्रता है। लेकिन इस तरह की राय जाहिर करना जिससे अश्रुतपन की परवरिश मिलती है यह डेमोक्रेसी के सिद्धांत के खिलाफ है। जब मैं इन बातों पर सोचने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में चक्कर आता है कि कौनसा इलाज हो जबदेस्त जो कि इस पाप को, इस कोढ़ को दूर कर दे। इसमें हम जरा भी कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं, इसमें हम जरा भी मुँह पुछोव्वल नहीं चाहते हैं, कोई तमाशा नहीं चाहते हैं। यह जो डेमोक्रेसी के नाम पर मुँह पीछा आता है, बुराई की परवरिश की जाती है उसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। मैं इस बीज को बोया नहीं कर सकता कि इस तरह का कोढ़ हमारे समाज में रहे। जैसा कि हमारे टामटा माहव ने कहा, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि इसमें हमारा दोष है। मैं उनकी इस बात को मानता हूँ कि जातिपात ही इसकी बुनियाद है। कैसे जातिपात उठे ? अभी भी हम छोटी छोटी बातों में जातिपात को इस तरह जगह देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी ख्याल नहीं देती है। अभी तक ऐसे फार्मों बने हुए हैं, जहाँ हर बात में जाति जरूर लिखाते हैं। अभी तक होश नहीं हुआ कि हम जातीयता को लिखना कानूनन हटा दें और फार्मों वगैरह में उनका लिखा जाना बन्द कर दें। कहीं मुकद्दमा होता है, नौकरी की बात होती है, स्कूल या कालिज में भर्ती का सवाल होता है तो जाति लिखो। स्वराज्य हो गया, राज्य करने के लिए हम बैठे हैं, अंगरेजों को कहते थे तुम हमको लड़ाते हो, हममें भेद पैदा करते हो, लेकिन आज हमारे हाथ में ताकत आ गई है तो वही काम कर रहे हैं जो अंगरेज कर रहे थे, उसी शीक पर

चलते हैं और उसी जाति के नाम पर नौकरी देते हैं। यह एक शर्म की बात है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि कैसी शर्मिन्दगी की बात है कि हमारी जो हरिजन वेलफेयर के नाम से संस्था है वह किस प्रकार जाति के नाम से कार्य करती है। हमारा जो अनाथालय है—यह सही बात है कि उसमें ज्यादातर लोग गिरी हुई जाति के हैं, ज्यादातर अछूत हैं, हरिजन हैं—तो हरिजन वेलफेयर वाले वहाँ गए, उन्होंने वहाँ की हालत को देखा और उनका हृदय द्रवित हुआ और चाहा कि हमें कुछ मदद करें। तो वह मदद करने के लिए उन्होंने शर्त करनी चाही कि आप अगर लिख दें कि ये हरिजन हैं तो हम आपको मदद दे देंगे। हमने कहा कि हमने हरिजन को खत्म कर दिया, हम हरिजन के नाम पर मदद नहीं कराना चाहते हैं। अब आप बताइए, अब हम अपनी संस्था के बच्चों को हरिजन कहलवायें तो हमें मदद मिले। हम अपनी संस्था के बच्चों के दिमागों में इस ख्याला की परवरिश करें कि वे हरिजन हैं। आप सोचें कि हम किस तरह हरिजनों को बनाते हैं। हमारी संस्था में हरिजन बच्चे जरूर हैं लेकिन आप जाकर देखिये वे कैसे गीता का पाठ करते हैं, कैसे संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आप नहीं समझ पायेंगे कि कौन ब्राह्मण है या किसी और जात का। लेकिन आप रुपया देने के लिये हरिजन जरूर बनाना चाहेंगे। अगर आप समझते हैं कि यह सरकारी नीति है, यह पालिसी है और इस तरह की पालिसी पर आप आंख बन्द करके चलते हैं तो परमात्मा ही रक्षा करे। समझ में नहीं आता हम किस भूलभुलैयाँ में हैं।

**श्री देव हीनन्दन नारायण :** परमात्मा भी रक्षा नहीं करेगा।

**श्री कै० बि० लाल :** हाँ परमात्मा भी रक्षा नहीं करेगा यह बात सही है। क्या हमने हरिजनों के लिये बहुत काम किया है, क्या कानून बनाकर अनाथबालिकाओं को उठाया है और हरिजनों को नौकरी में फैसिलिटी दी

है ? उनको पढ़ाने में, स्कूल और कालिजों में फैसिलिटी दी है ? उनको और जगहों में रिप्रेजेंटेशन दिया है ? हाँ, है लेकिन सलेचर में आने में और बहुत सी बातों में हमने उनको सहूलियतें दी हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये सहूलियतें देकर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। असली बात जो है वह है अछूतपन को खत्म करने की। जिस समय छुआछात हमारे देश के लिए एक समस्या बन गई थी तब गांधी जी ने "हरिजन" शब्द की बनावट इस जाति के लोगों के लिये की थी। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि अरे, यह भी एक नयी जाति पदा हो गई है। लेकिन अब हम इस 'हरिजन' शब्द को कब तक रखना चाहते हैं ? मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी पालिसी में कब तक यह चीज है उनको हरिजन रखना। यह पहले बताइये। यह रिप्रेजेंटेशन तो खर दस साल, बीस साल, बाहिर है होना ही चाहिये लेकिन इस प्रस्ताव के जरिये से नहीं। यह तो आपकी अक्लमन्दी से होना चाहिये था। पहले आप सहूलियत से राज भोज साहब को बुला लें। लेकिन आपको बाद में अक्ल होगी, बाद को वही बात होने वाली है। राज भोज साहब तो बहुत आनरेबली अपने प्रस्ताव को विदवा कर लेंगे। अच्छा होता कि गवर्नमेंट की नीति में अगर यह बात रहती कि ऐसी बातें सामने न आयें जिनसे देश का वातावरण बिगड़ने पावे। डेमोक्रेटिक तरीके पर आप उनको बुलाकर और चाहे एक एड-वाइजरी कमेटी कायम करके आप तय करते कि साहब इस चीज को हमें करना है। लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर इस सदन के अन्दर छोट्टालेदर होती है। इस सदन के अन्दर इस तरह की बातें हों, हरिजनों को कायम रखने की बात की जाय, अछूतपन को सींचने की, परवरिश करने की बात हो, यह बहुत दुःखदायी चीज लगती है : इसमें कंप्रोमाइज करने से परवरिश करने से वही चीज पैदा होगी जो चीज कि जिन्ना साहब ने पदा की थी। जिन्ना साहब भी बहुत बड़े नेशनलिस्ट हुए हैं।

श्री पा० ना० राजभोज : वे अपने को से रेट नेशन का मानते थे ।

श्री कै० बि० लाल : घबड़ाइये नहीं वही चीज हम भी देखने लगेंगे अगर यही मनोवृत्ति रही तो । अभी तो वह वृक्ष है, उसका फल हम आगे चल कर देखेंगे । ऐसा लोगों के मुंह से हमने सुना है कि हरिजन-स्थान होना चाहिये हम दूसरी कौम हो जाना चाहते हैं, हमारे लखनऊ के वे मित्र अभी तक लोक-सभा में मौजूद हैं, कुरील साहब । उन्होंने इसी बात को पुरानी एसेम्बली में कहा था । अब वे सही रास्ते पर आ गए । उनकी हमारी दोस्ती है और किसी मुखालिफ़्त की वजह से मैं यह नहीं कह रहा हूँ .(Time bell rings.) अम्बेडकर साहब कहते थे यह दिव्स्ट आफ़ माइंड है । उस मनोवृत्ति में यह चीज पैदा होती है । जिन्ना साहब बड़े नेशनलिस्ट थे उनके विचारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं । वे अपना माथा ठोकर कहते थे 'इन हिन्दुओं को कभी अक्ल नहीं आयेगी ।' मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बतलाता कि क्यों सचमुच में जिन्ना साहब अपना कपाल ठोकते थे कि हिन्दुओं को अक्ल कब आयेगी । हम यह बात भले ही कहें कि हम सेपरेटिस्ट टैंसी पर नहीं चलते हैं लेकिन रास्ता वही है जिस रास्ते पर आप कदम रखते हैं यह वही रास्ता है जिससे आप शिङ्गुल्ड कास्ट को बनाते हैं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हरिजनों का विरोध करता हूँ कि उनको जगहें नहीं मिलनी चाहियें । मैं मानता हूँ कि उनको काफी जगहें मिलनी चाहियें । जो जगहें अभी तक उनको मिलती रही हैं उनको सुरक्षित रखने के वास्ते आपको रास्ता निकालना चाहिये और वह रास्ता आपको सुभीते से निकालना चाहिये न कि वातावरण को बिगाड़ कर ।

मैं इस संकट में हूँ कि मैं समर्थन करूँ तो किसका करूँ । प्रस्ताव का करूँ या इसके भाग का ? प्रस्ताव के भाग का तो समर्थन

करता हूँ लेकिन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहता जैसा कि मलकानी साहब ने कहा है ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GOVIND BALLABH PANT): Sir, this is a simple Resolution. Its purpose has been fully stated by the mover. The Resolution asks for the extension of the period provided for reservation of seats for scheduled castes in the legislatures under article 334 by 10 years. The Constitution at present does not admit of any such reservation after the expiry of 10 years. That period of 10 years will expire in 1960; however, it is laid down that they will not be expected to be withdrawn at the end of this period of 10 years but this system will continue till the dissolution of the House. That means, that they will have the benefit of reservation till 1962 but thereafter if the Constitution remains unamended in its present form, then there will be no reservation for scheduled castes or scheduled tribes. Shri Rajabhoj has confined his Resolution to Scheduled Castes only.

SHRI P. N. RAJABHOJ: No, the Scheduled Tribes also are there, in the amended Resolution.

SHRI GOVIND BALLABH PANT: You have amended it? Well, I am glad; otherwise it would be difficult to discriminate against Scheduled Tribes. That is, however, a minor point.

I imagine, that hon. Members of this House are familiar with the history of this problem. I do not want to go back to the pre-independence period, to the epic fast of Mahatma Gandhi, or to other matters. I recognise, however, that the Scheduled Castes are today not in a position to stand on their own legs and to occupy such a position as would enable them to hold their own against other sections of the community. When the Constitution was framed, a Minority Committee was appointed, which was presided over by Sardar Patel. At one stage it was decided that the minorities should have seats reserved for them in accordance with their population,

that is to say, the seats for every minority should bear the same proportion to the strength of a legislative body as their population bore to the total population of the country. The principle of separate electorate was condemned by all unanimously, yet, reservation for all minorities was accepted. Later on, the minorities themselves felt that it would not be in their interest to have any such special treatment and they agreed to rub shoulders with others and to have no reservation for themselves. Muslims, Christians and Sikhs alike, all of them agreed to seek elections and not to have any sort of protection for themselves in any shape or form. It was, however, realised that the Scheduled Castes stood in a different category, that, though they too formed a minority, they formed perhaps the weakest section in our community. Similarly the Scheduled Tribes also held a very weak position. Accordingly reservation for a period of ten years was provided. The Bill relating to the Constitution was then being piloted by Dr. Ambedkar. Amendments of various types were moved, but no change in the proposal that was initiated by the Government was accepted, and that 'proposal' is now embodied in the Constitution. I understand that Mr. Rajabhoj has succeeded in securing the sympathy of many Members of this House to his Resolution. I am not surprised, for he is one of the Members who espouses the cause of the Scheduled Castes with his unrivalled earnestness, and he gets a ready response. So far as I am concerned, I had occasion to make a statement in the Lok Sabha in this regard just two days ago. I stated a minute ago that the present arrangement will continue till 1962. The question at present is not important or urgent. We will give earnest consideration to the proposal made by Shri Rajabhoj, and as I submitted just now, I personally feel that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes still continue to be very weak links in our national chain. So I would like them to gain fresh strength and we would like to do all that we reasonably can to enable them to stand on their own

legs and to be able to join others on terms of equality, social, political and economic. So the matter will be given very earnest thought, but there is no urgency about it. A decision will be taken before 1962 and if it is intended to extend the period, then a Bill will have to be introduced in Parliament for amending the existing article of the Constitution. In any case, we will approach Parliament for the expression of its opinion on this subject before the expiry of the period now available for reservation, and we will be guided by the views of Parliament. We will in the meantime give thought to it, and we hope to be able to place the considered opinion or proposals of Government before Parliament.

In view of what I have said, I trust the mover will be pleased to withdraw his Resolution.

4 P.M.

**श्री पा० ना० राजभोज :** उपसभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव मैंने रखा है इसका पंत जी ने, पंडित कुंजरू जी ने, अलगूराय शास्त्री जी ने, अग्निभोज जी ने, टामटा जी ने और दूसरे बहुत से प्रमुख सदस्यों ने समर्थन किया, इसमें मुझे बहुत सन्तोष हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के भाई राम सहाय जी ने इसका बहुत अच्छी तरह से समर्थन किया है।

इस प्रस्ताव को मदन के समक्ष रखने का मेरा यह मतलब नहीं है कि मैं कोई सेप्रेट एंटीटी चाहता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि जब मेरा ऐसा ख्याल था, लेकिन जब हमारे देश का सिर ऊंचा हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम हमेशा हरिजन न बने रहें। यह सोचना कि बुरी तरह रहने में हमको सन्तोष होगा, यह गलत बात है। कई लोगों का यह ख्याल है कि हम जातियाँ बढ़ा रहे हैं, यह भी गलत बात है। जब गांधी जी से डा० अम्बेदकर ने यह कहा था कि हम सेप्रेट इलेक्ट्रेट चाहते हैं तो मैंने उनका विरोध किया था। मैंने यवेंदा पेंवट में गांधी जी की हर प्रकार से मदद की थी। मैंने इस बात के

**[श्री पा० ना० राजभोज]**

लिए आन्दोलन किया था और यह कहा था कि हम हिन्दुओं से अलग नहीं रहेंगे बल्कि हम हिन्दुओं के साथ रह कर सब प्रकार की तरक्की करेंगे। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह राजनीति थी कि हम हिन्दुओं से अलग हो जायें, लेकिन उनकी राजनीति सफल नहीं हुई। उसी समय से मैं दलित-वर्गीय भाइयों की सेवा कर रहा हूँ। मैं तीस वर्ष से यह कार्य कर रहा हूँ और सब तरह के आन्दोलनों में भाग लिया है और त्यागपूर्वक कार्य किया है। मैं यह चाहता हूँ कि यह कार्य हृदय परिवर्तन से और मत-परिवर्तन से होना चाहिये। एक ऐसा भी समय था जब मैंने अनेक बार सत्याग्रह किया था और गाली वगैरह दी थी लेकिन उसके लिए मुझे दुःख है। अब मैं यह चाहता हूँ कि यदि यह सवाल शान्ति से और मे से हल हो जाये तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम हमेशा चमार, महार, धड़े आदि बने रहें और हमारी बस्ती अलग रहे। पन्त जी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी बैठी थी और उसमें मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि हरिजनों के होस्टल अलग नहीं होने चाहिये। हरिजनों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था और कुछ सम्पर्क का काम भी हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज भी पुराने स्कूल के लोग सब जगह हैं हममें भी हैं और हिन्दू समाज में भी हैं। हमारे श्री कैलाश बिहारी साहब को ही ले लीजिये। वे कभी विरोध करते हैं और कभी बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरह से हम में भी ऐसे लोग हैं जिनकी बातों से कभी कभी हमें बड़ा दुःख होता है।

बहुत से लोगों ने कहा कि इस जातपात के प्रश्न ने बहुत नुकसान किया है। हमारे देश

में हजारों जातियाँ हैं लेकिन जब ऊपर की जातियाँ नष्ट हो जायेंगी तो नीचे की जातियाँ अपने आप खत्म हो जायेंगी। श्री महेश सरन जी ने कहा कि यह ठीक नहीं है। मैंने भी एक भारत दलित सेवक संघ की तरफ से कमला नेहरू ग्ल्स होस्टल सिद्धार्थ खोला है और उसमें ब्राह्मण, मरहटा और सब जाति के लोगों को रखा है। शुरू शुरू में जब मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया उसी वक्त मैंने यह निश्चय किया कि जाति जाति के अलग रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब तक यह प्राबल्य है, यह सवाल है, बड़ी शान्ति से यह काम करने की आवश्यकता है। इसीलिये मैंने अपने सिद्धार्थ और कमला नेहरू होस्टल में दूसरी जाति के विद्यार्थियों को रखा। पहले मैं भी सांप्रदायिक मनोवृत्ति का था, जिन्ना टाइप था। यह सब लोग जानते हैं कि मेरे क्या विचार थे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आदमी यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि जो मैं कह रहा उससे क्या होगा, जो मैं गाली गूली दे रहा हूँ उससे क्या होगा। यह बात जरूर है कि मैं स्वाभिमान रखना चाहता हूँ। हमारे प्रोफेसर मल्कानी साहब ने कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हम यह मांगें, हम वह मांगें।

**श्री ना० र० मल्कानी :** मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि और मांगो।

**श्री पा० ना० राजभोज :** बहुत अच्छी बात है। हम भी इस ढंग से मांगना नहीं चाहते हैं। यह हम भी जानते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। डाक्टर अम्बेदेकर के सम्बन्ध में गांधी जी ने यह कहा था कि अम्बेदेकर साहब अगर गाली देते हैं तो जो हमने पाप किया है उसी का बदला मिल रहा है। यह कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आप इस भावना से काम करेंगे तभी देश का सिर ऊँचा होगा। बहुत से लोग यह कहते हैं कि महार, चमार या दूसरे हरिजन



धर्म बदल लेंगे तो अस्पृश्यता खत्म हो जायगी। बहुत से चमार मुसलमान बन गये, बहुत से महार मुसलमान बन गये, बहुत से बौद्ध बन गये बहुत से ईसाई बन गये और बन रहे हैं लेकिन इससे क्या उनकी आर्थिक दशा में कोई सुधार हुआ ? जहां तक मेरा विचार है उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। धर्म आध्यात्मिक उन्नति का साधन है आर्थिक उन्नति का नहीं।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हर जगह जाता हूं और यह देखता हूं कि हमारी काम करने की जो मशीनरी है वह ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। हमारी सरकारी मशीनरी का जो काम करने का ढंग है वह बहुत गलत है। हमारे भाई राम सहाय जी ने यह कहा कि चपरासी चमार क्यों नहीं रखे जाते हैं ? यदि ऐसा किया जाय तो इससे जात-पात का मामला खत्म होगा। आज होता यह है कि अगर कोई ठाकुर आफिसर है तो वह ठाकुर चपरासी रखता है, अगर कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण रखता है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए और भी बहुत से ढंग हैं। आप अपने घर में एक एक हरिजन और आदिवासी विद्यार्थी रखिये और उसको पढ़ाइयें। लेकिन ऐसा कौन करता है ? आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप कहते हैं कि जमाना बदल रहा है लेकिन आप देखिये कि हमारे भाई बाल्मीकि जी ने लोक सभा में क्या कहा है। मैं उनके भाषण का कुछ हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

“इसी तरह से त्यागी गांव के अन्दर एक १७ वर्ष का भंगी का लड़का जिसका कि नाम ओमप्रकाश था और जो बनिये, जाट और ठाकुरों के लड़कों के साथ पढ़ता था, चूंकि वह जरा कुछ अच्छे ढंग से पढ़ता था और नम्बर ज्यादा लेता था उसको कत्ल करके उसकी लाश को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया और बाद में बिना किसी इन्क्वायरी के उस

लाश को जला दिया गया और आज भी गांव वाले लोग उस हरिजन भंगी को ललकार कर कहते हैं कि जा लिवा ला अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट को, तेरे परावठे इंजन के आगे उड़ते हैं।”

इसी तरह की एक घटना मैं यहां हाउस में और सुनाना चाहता हूं। चांदौख गांव में वहां जो ठाकुर लोग बड़ी अकड़ के साथ रहते हैं उन्होंने एक १२ साल के चमार के लड़के को चार बजे से लगाकर २ बजे तक इतना मारा पीटा कि उस बच्चे का दम निकल गया, उसका मुकद्मा कोर्ट के अन्दर मौजूद है। यह घटनाएं ऐसी हैं जिनको कि सुनकर दिल में एक दर्द पैदा होता है।

अब गांव से जरा शहरों की ओर चलिये। खुर्जा जंक्शन पर रेलवे के नल के ऊपर एक भंगी ने जरा सा हाथ एक ठेकेदार के लड़के के लगा दिया तो उस बेचारे भंगी का सिर और हाथ तोड़ डाला गया और उसको लेकर रेलवे मैजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुकद्मा चल रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिनको अगर इकट्ठा किया जाय और सुनाया जाय तो वह भागवत गीता हो जायगी। मैं इस समय ऐसी भागवत गीता पढ़ कर हाउस का समय लेना नहीं चाहता।

हमारे एक मुसलमान भाई ने यह कहा कि हरिजनों का मामला ठीक हो रहा है। मैं भी यह नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिये कि सब स्टेट्स में कई प्रकार के कानून पास हो चुके हैं :

Bihar Harijan Act, 1949; The Bombay Harijan Act, 1946; Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947; Central Provinces Scheduled Castes Act, 1957; C.P. and Berar Temple Entry Act; East Punjab Act; इसी प्रकार मद्रास, उड़ीसा, यू० पी०, बंगाल हैदराबाद, मध्य प्रदेश, मैसूर सौराष्ट्र द्रावकोर कोचीन और कुर्ग में ऐक्ट पास हो चुके हैं और काम हो रहा है। मैं नहीं कहता कि कुछ

नहीं हुआ लेकिन अभी शुरूआत हुई है। अभी स्टेट्स में जैसा काम होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है। यहां से लाखों रुपये की ग्रांट दी जाती है लेकिन फिर भी ठीक काम नहीं होता है। आज हरिजनों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। यह मैं मानता हूं कि आज सोशल वेल्फेयर का काम हो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा हो रहा है। अब जबकि हम आजाद हो गये हैं तब भी अगर हमारा हर समय यह खयाल बना रहे कि हम चमार हैं, हम महार हैं, हम हरिजन हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। यहां शहरों में आप लोग हमारे साथ सहानुभूति दिखलाते हैं लेकिन देहातों में जो उच्च जाति के लोग हैं वे हमको तकलीफ देते हैं। जो ठाकुर लोग हैं, जो मरहटे हैं वे हमसे कहते हैं कि तुम क्यों खटिया पर बैठते हो, क्यों घोड़े पर चढ़ते हो, क्यों अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। उनको हमारा उत्कर्ष अच्छा नहीं मालूम होता है। इस प्रकार यह कई तरह की बीमारी है। इस बीमारी को नष्ट करने के लिये महात्मा गांधी ने कार्य किया, कई लोगों ने कार्य किया और अस्पृश्य लोगों ने कार्य किया। लोग कहते हैं कि अस्पृश्य लोग हरिजनों के लिये ज्यादा काम करें। अरे साहब, हजारों वर्ष से हरिजन गुलाम रहे हैं और अभी कुछ थोड़े बहुत लोग ही आगे बढ़े हैं। हालत यह है कि लोगों के दिमाग में और पेट में दर्द पैदा हो जाता है कि अरे यह तो वकील बन गया, यह एम० पी० बन गया, यह बन गया, वह बन गया। इसलिये मेरा कहना है कि यह बीमारी जो है वह बहुत बड़ी है और जो पुराने खयाल के लोग हैं, सड़े हुये बिचार के लोग हैं उनको हमारे आगे बढ़ने से दुःख लगता है। मुझे अफसोस है कि मुझे ऐसा कहना पड़ता है, ऐसी खराब बात बोलनी पड़ती है। मेरे में कई त्रुटियां हैं, फिर भी मुझ से जो कुछ हो सकता है वह करता हूं। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूं और बदल रहा हूं। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे इलाहाबाद

वाले श्री सरण भाई हरिजन आश्रम चलाते हैं।

**श्री किशोरी राम :** बहुत रुपया खा रहे हैं।

**श्री पा० ना० राजभोज :** यह बात ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिये। मेरा तो यह कहना है कि आपको भी बहुत ज्यादा काम करना चाहिये और हमें अपने पांवों पर खड़े हो कर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। दूसरे के हाथ से पानी पिलावें या दूसरे के हाथ से खाना खिलायें यह बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों और दलित जातियों में आजीवन सेवक हों। जैसे कि 'सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी' के कुंजरू साहब बैठे हुये हैं वैसे ही आदिवासियों और दलित जातियों में से हमारे भारत दलित सेवक संघ की तरफ से अगर ५० भी आजीवन सेवक बन जायें तो बहुत कुछ काम हो जाय और वे आदिवासी और हरिजनों के लिये काफ़ी सेवा का काम करेंगे उसी बल से मैंने संस्था स्थापन की है। लेकिन आज तो हर एक आदमी लीडर बनना चाहता है। लीडर बनने से काम नहीं होता है, सेवा करने से काम होता है।

**श्री रामेश्वर अग्निभोज :** आप भी तो लीडर हैं।

**श्री पा० ना० राजभोज :** मैं लीडर नहीं हूं। मैं तो सेवा की दृष्टि से काम करना चाहता हूं। अग्निभोज जी भी बड़ा काम करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा और अच्छा काम करें। मैं तो जबान में सुधार करना चाहता हूं। जबान की वजह से कभी कभी नुकसान हो जाता है लेकिन क्या करें, बहुत से हजारों प्रकार के दुःख

हैं और करुण कहानियां हैं। इसी वास्ते मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वे अमल में आनी चाहियें। जो फाइव ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हमको आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, सभी दृष्टियों से सभी प्रकार की सहायता मिलनी चाहिये। ज़मीन के बारे में भी बहुत कुछ सहायता मिलनी चाहिये। भूदान यज्ञ में भूदान के लिये बहुत कुछ हो रहा है और उसको हमारे विनोबा जी चला रहे हैं लेकिन अगर वह स्थगित करें, और एक वर्ष तक हमारे हरिजनों के लिये काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सब दृष्टियों से काम होना चाहिये।

(Time bell rings.)

उपसभापति महोदय, आपकी घंटी जब चुकी है और मुझे बहुत सी बातें बोलनी थीं लेकिन मुझे इस वक्त गांधी जी की बात याद आ गई है इसलिये उसको तो ज़रूर ही कहूंगा। इसके बाद और ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब मैं साबरमती आश्रम में था तब गांधी जी ने लिखा था :

“भाई राजभोज,

मेरे उपवास से तुम धबराहट में नहीं पड़ना। वहीं रहो और ज्ञानमय सेवा के लिये तैयार हो लो। मैं जिन्दा रहा तो इसी शरीर से सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मर गया तो भी भगवान की दया समझूंगा। देह पड़ने से मेरी सेवा खत्म नहीं होगी। हरिजन सेवा का जो काम आरम्भ हुआ है वह कभी बन्द नहीं हो सकता है। अनशन करते

हुये हजारों सवर्ण हिन्दुओं का प्राणन्याय हो जाय तो भी मैं उसे अधिक नहीं समझूंगा। मैं तो शायद ही लिख सकूँ, तुम ही लिखते रहना। बापू के आशीर्वाद।”

उन्हें हम लोगों से कितना बड़ा प्रेम था और उन्होंने हिन्दुस्तान में बहुत काम किया। ठाकुर बप्पा साहब ने भी बहुत काम किया और अम्बेडकर साहब ने भी किया। तो काम करने का यह तरीका रहता है और इस तरीके से हमारा काम होना चाहिये। होम-मिनिस्टर साहब ने हमें एक आवासन दिया है और हम इसके लिये उनको धन्यवाद देते हैं। जब तक हमारे प्राइम-मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और होम-मिनिस्टर पंत के नेतृत्व में हमारे देश का और हमारी सरकार का जो कुछ काम हो रहा है वह ठीक तरह से होता है तब तक मैं चाहता हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन करूँ और उनके ऊपर विदवास करूँ। हमारा यही फ़र्ज है और मैं क्या कर सकता हूँ? आदिवासियों और हरिजनों को ऊपर उठाने का जो सवाल है उसके लिये उनके कोऑपरेशन के बिना मैं क्या कर सकता हूँ। इस काम में उनका भी कोऑपरेशन चाहिये और आप सब मैम्बरान लोगों का भी कोऑपरेशन चाहिये। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अपोजीशन के लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ एक दो आदमियों ने इसके खिलाफ़ बोला है लेकिन उनको ज्यादा महत्व देने से कोई लाभ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। उपसभापति महोदय, आपने मेरे भाषण को बड़ी शान्ति से सुना इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

**उपसभापति :** आप क्या यह प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

**श्री पा० ना० राजभोज :** जी हाँ, मैं उसको वापस लेता हूँ। माननीय गृह-मंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया है उसको ध्यान में रखते हुये मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw the Resolution?

(No hon. Member dissented.)

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three other Resolutions. Mr. Mahabir Prasad is not here. Mr. Raja-bhoj, are you moving your next Resolution?

**श्री पा० ना० राजभोज :** जो मुझे आश्वासन दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुये मैं इस दूसरे प्रस्ताव को कैसे मूव कर सकता हूँ। जब माननीय पंत जी ने इतना आश्वासन दे दिया है तो मैं इस प्रस्ताव को कैसे मूव कर सकता हूँ। मैं इसको मूव नहीं करना चाहता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: **You** are not moving. Shrimati Savitry Devi Nigam is not here. There is no other business before the House. The House stands adjourned till six o'clock for the presentation of the Budget.

The House then adjourned at fifteen minutes past four of the clock till six of the clock.

The House reassembled at six of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

#### THE BUDGET (GENERAL), 1958-59

THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): Sir, I beg to lay on the Table a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 1958-59.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned **till 11 A.M.** on Monday.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 3rd March 1958.